

दैनिक विनय उजाला

● मुंबई, ठाणे, नई दिल्ली, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, आलीराजपुर से एक साथ प्रकाशित

मूल्य ₹ 2.00

RNI. Reg. MHHIN/25/A2524

मुंबई

शनिवार, 25 जुलाई 2026

आषाण शुक्ल पक्ष-11

वर्ष : 01 | अंक : 337

कुल पृष्ठ : 08

पहली ही गेंद पर विकेट, मयंक ने रचा इतिहास... 07

न डरते हैं, न डराते हैं, सच सामने लाते हैं..!

पीएम मोदी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना

सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद तोड़ा अनशन

नई दिल्ली,एजेंसी

सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को 26 दिन बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह तथा लेह लद्दाख की शीर्ष संस्था के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी।

एक्स पर एक पोस्ट में वांगचुक ने कहा कि यह कदम विभिन्न शर्तों पर लंबे समय तक चली बातचीत और देश में संभावित हिंसा को देखते हुए उठाया गया है। वांगचुक ने कहा, अभी-अभी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह तथा लेह लद्दाख की शीर्ष संस्था के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने 26 दिन बाद अपना अनशन तोड़ा। इस बीच मैं आप सभी से अपील करता हूं कि किसी भी जगह किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन वापस पाने की अपील की। यह अपील सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा 26 दिन बाद अपना अनशन खत्म करने के बाद की गई।



दिल्ली में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द

दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोज जनता पार्टी का आंदोलन जारी है। जिसे देखते हुए पुलिस-प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। यह आदेश सभी रैंक के अधिकारियों के लिए जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी आदेश में लिखा है कि मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक कोई भी सामान्य छुट्टी आदि नहीं दी जाएगी।

पीएम ने कहा- पेपर लीक पर कैबिनेट सख्त फैसला लेगी



प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाएगी। पीएम ने बताया कि कैबिनेट में इससे जुड़े मसौदे पर चर्चा होगी और सख्त फैसले लिए जाएंगे। मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही इसे जल्द पास कराने की कोशिश होगी। वीडियो में मोदी ने कहा, दोस्तों, मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई सामान्य मामला नहीं है। लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए यह बेहद पीड़ादायक है। और इसलिए, पिछले ढाई महीनों में पेपर लीक की घटनाओं के बाद कई बड़े कदम उठाए गए हैं। दोषियों को पकड़ लिया गया है और वे फिलहाल जेल में हैं।

मुंबई 'भारत टैक्सी' सेवा का शुभारंभ

'भारत टैक्सी' से यात्रियों के लिए खुलेगा नया सफर - सीएम

मुंबई, एजेंसी

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे परिसर में केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री फडणवीस ने 'भारत टैक्सी' सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 'भारत टैक्सी' सहकारिता क्षेत्र की नई क्रांति है, जो यात्रियों को सुरक्षित, पारदर्शी और किफायती यात्रा उपलब्ध कराएगी, वहीं चालकों को सम्मानजनक आय और स्वामित्व का अवसर देगी। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में शुरू किया गया यह मॉडल देशभर में नई मिसाल बनेगा। सीएम ने कहा कि ओला और उबर जैसी निजी एग्रीगेटर कंपनियों ने परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन त्योहारों और बारिश के दौरान अत्यधिक किराया तथा चालकों से भारी कमीशन वसूले जाने से यात्रियों और ड्राइवरों दोनों को परेशानी होती थी।



स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवी मुंबई हवाई अड्डा क्षेत्र के स्थानीय निवासियों और परियोजना प्रभावित परिवारों के युवाओं को इस सेवा से बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने डिजिटल हस्ताक्षर आधारित एग्रीगेटर नीति लागू की है और सभी वित्तीय लेन-देन पर सहकारिता विभाग की निगरानी रहेगी। पहले चरण में 600 टैक्सियां शुरू की गई हैं और जल्द ही इनकी संख्या 1,000 से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है।

पुणे और नागपुर में भी जल्द शुरू होगी सेवा

केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ ने कहा कि सहकार टैक्सी संस्था के माध्यम से चालक अब कर्मचारी नहीं, बल्कि संस्था के सदस्य और मालिक बन गए हैं। संस्था के लाभांश का पैसा सीधे चालकों के खातों में जाएगा। उन्होंने बताया कि देशभर के लगभग 8 लाख चालक इस संस्था से जुड़ चुके हैं और अब तक 77 करोड़ रुपये बिना किसी कमीशन के सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं।

बेरोजगारों को मिलेंगे नए अवसर

राज्य के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटील ने कहा कि सहकारिता केवल संस्थाएं चलाने का माध्यम नहीं, बल्कि आम लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रभावी साधन है। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी के माध्यम से डिजिटल बुकिंग, पारदर्शी लेन-देन, सुरक्षित यात्रा और किफायती किराया उपलब्ध होगा। इससे हवाई अड्डे से मुंबई आने-जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी और हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।

एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली 'कुशा' का सफल परीक्षण

बालासोर, एजेंसी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलप्रणाली 'कुशा' का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया।

कुशा मिसाइल प्रणाली को लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और बड़े दुश्मन विमानों सहित विभिन्न हवाई खतरों को लंबी दूरी और अलग-अलग ऊंचाई पर नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'कुशा' प्रणाली के पहले सफल उड़ान परीक्षण पर डीआरडीओ को बधाई दी और इसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि बताया। सफल परीक्षण भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां विकसित करने की देश की क्षमता को दर्शाता है। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'कुशा' का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया।



ईडी ने दिल्ली, यूपी और पंजाब में 8 ठिकानों पर छापेमारी की

नई दिल्ली, एजेंसी

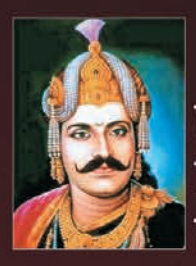
प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को सेंटोष ओवरसीज लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ चल रही लगभग 450 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में आठ स्थानों पर तलाशी ली। सुबह से कंपनी के प्रमोटरों, संबंधित संस्थाओं और सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी का लखनऊ जोनल कार्यालय धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चला रहा है। ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो के एक मामले से जुड़ी है, जिसमें बैंकों के एक समूह से लगभग 450 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आया है कि ऋण की राशि कथित तौर पर फर्जी चालानों और पैसों के लेनदेन को घुमाने के जरिए शेल कंपनियों, फर्जी लेनदेन कराने वाले ऑपरेटरों और संबंधित कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से दूसरी जगह भेजी गई और कई स्तरों पर घुमाई गई।

13th

राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2026

दैनिक विनय उजाला

पहली बार विशेष सम्मान



राजा विक्रमादित्य सम्मान



महाकवि कालिदास सम्मान



समाजसेवी स्व. पूनमचंद यादव सम्मान

विशिष्ट अतिथि



श्री गौतम टेटवाल
प्रभारी मंत्री, उज्जैन



श्री अनिल फिरोजिया
सांसद, उज्जैन



श्रीमती कलावती यादव
सभापति नगर निगम, उज्जैन



श्री नन्दलाल यादव
कार्यक्रम संरक्षक एवं अध्यक्ष, प्रेस क्लब, उज्जैन



प्रदेश के गौरव और लोकप्रिय मुख्यमंत्री

डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मप्र शासन



डॉ.विनय मिश्रा
प्रकाशक

दिनांक: रविवार, 06 सितंबर 2026
समय : दोपहर 11.30 बजे

स्थान: रामसखा गौतम सभागृह, भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र, उज्जैन (म.प्र.)



विशाल हाड़ा
संयोजक

धर्मेन्द्र भाटी
स्थानीय संपादक

पराग पांचाल
स्थानीय प्रबंधक



अति विशिष्ट अतिथि

पद्मिनी कोल्हापुरे
सुप्रसिद्ध सिने तारिका

संक्षिप्त समाचार

भिवंडी में ड्रग्स माफियाओं पर बड़ा प्रहार : नाइजीरियन महिला गिरफ्तार, 2.06 करोड़ रुपए की एमडीएमए बरामद



रश्मी पांडे/ भिवंडी। भिवंडी ग्रामीण पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 2.064 किलोग्राम एमडीएमए नामक प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत ?2 करोड़ 6 लाख 40 हजार बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुंजन पुलिस थाना की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक महिला बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर क्षेत्र में आने वाली है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से भारी मात्रा में एमडीएमए ड्रग्स बरामद हुई। गिरफ्तार महिला की पहचान नाइजीरिया की 26 वर्षीय नागरिक के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि बरामद ड्रग्स की खेप कहां से लाई गई थी, इसे किसे पहुंचाया जाना था और इस अंतरराज्यीय अथवा अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं। मामले को लेकर कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है। भिवंडी ग्रामीण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि मादक पदार्थों की तस्करी या बिक्री संबंधी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। नशे के सौदागरों के खिलाफ भिवंडी ग्रामीण पुलिस की यह कार्रवाई जिले में ड्रग्स माफियाओं के लिए बड़ा संदेश मानी जा रही है।

बदलापुर में महावितरण की लचर व्यवस्था से नागरिक परेशान, सुधार की मांग तेज

विनय उजाला, बदलापुर। कुळगाव-बदलापूर परिसर में पिछले कई दिनों से बार-बार बिजली आपूर्ति खंडित होने से नागरिकों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। एक तरफ लगातार लाइट जा रही है, तो दूसरी तरफ बढ़े हुए बिजली बिलों ने लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश या हवा चलते ही बिजली गुल हो जाती है। घंटों तक सप्लाई नहीं आती, जिससे व्यापारियों, विद्यार्थियों और गृहिणियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। रात के समय बिजली जाने से बुजुर्ग और बच्चों की हालत और खराब हो जाती है। नागरिकों ने आरोप लगाया कि महावितरण की ओर से कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। शिकायत करने पर सिर्फ आश्वासन मिलता है, समाधान नहीं। वहीं दूसरी ओर मनमाने बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। नागरिकों ने मांग की है कि महावितरण जल्द से जल्द जर्जर तारों और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करे और लोडशेडिंग की समस्या का स्थायी समाधान निकाले, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा।

उल्हासनगर में जिला स्तरीय सुब्रतो फुटबॉल कप 2026-27 स्पर्धा उत्साह के साथ संपन्न

विनय उजाला उल्हासनगर। ठाणे जिला क्रीडा परिषद और जिला क्रीडा अधिकारी कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल स्पर्धा 2026-27 का आयोजन 21 जुलाई से 22 जुलाई तक उत्साहपूर्वक किया गया। यह स्पर्धा उल्हासनगर के छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में संपन्न हुई। स्पर्धा में जिले के 14 वर्ष और 17 वर्ष आयु वर्ग के दर्जनों स्कूलों की टीमों ने भाग लिया। बालकों के साथ-साथ बालिकाओं की टीमों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उद्घाटन समारोह में जिला क्रीडा अधिकारी, क्रीडा मार्गदर्शक और कई मान्यवर उपस्थित थे। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि सुब्रतो कप जैसे मंच से ही भविष्य के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार होते हैं। फाइनल मुकाबले में विजेता टीमों को ट्रॉफी और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। चयनित खिलाड़ी अब विभागीय स्तर पर ठाणे जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर आयोजकों, पंचों, कोच और बड़ी संख्या में क्रीडा प्रेमी उपस्थित थे।

तलोजा में सहायक अभियंता 50 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार



नवी मुंबई/रेनू पांडेय। नवी मुंबई एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एमएसडीसीएल (ख्स्श्वष्टस्रु), तलोजा में कार्यरत सहायक अभियंता रोहित मोरे को 50 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई नवी मुंबई एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक धर्मराज सोनके के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक अंजाम दी गई। आरोप है कि पी.एन. इलेक्ट्रिकल कंपनी के कार्य का फिजिबिलिटी रिपोर्ट देने के बदले सहायक अभियंता ने 50 हजार की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और तलोजा में कार्रवाई के दौरान आरोपी अधिकारी को रिश्वत की रकम स्वीकार करते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसीबी की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

नीति आयोग के सतत विकास सूचकांकों की समीक्षा बैठक



मुंबई, एजेंसी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए कि नीति आयोग द्वारा तय किए गए सतत विकास लक्ष्यों के सभी सूचकांकों में महाराष्ट्र को देश में शीर्ष स्थान दिलाने के लिए अगले चार वर्षों तक विभागवार और परिणाम आधारित योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आकांक्षी घोषित 10 जिलों और 177 तालुकों में नीति आयोग के सूचकांकों के अनुरूप बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जाएं, ताकि महाराष्ट्र देश में सबसे आगे रहे। सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने सामाजिक क्षेत्र वॉर रूम के तहत नीति आयोग के 17 सतत विकास सूचकांकों पर राज्य की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य की क्षमता को देखते हुए वर्ष 2030 तक और तेज गति से आगे बढ़ने के लिए नीति आयोग के विभिन्न सूचकांकों पर अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगले चार वर्ष राज्य के विकास के लिए निर्णायक होंगे। इस दौरान योजनाओं का पुनर्गठन और उन्हें अधिक मजबूत बनाया जाए। आगामी बजट योजना भी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को गति देने वाली होनी चाहिए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने सूचकांकों का गहन अध्ययन करें और बेहतर परिणाम के लिए कार्यप्रणाली व नीतियों में आवश्यक सुधार करें। अन्य अग्रणी राज्यों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और नीतियों का अध्ययन कर राज्य के प्रदर्शन को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए रियल टाइम डेटा का संग्रह, विश्लेषण और अन्य राज्यों के आंकड़ों से तुलना आवश्यक है। राज्य में डेटा संग्रहण प्रणाली को और मजबूत किया जाए तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का लगातार मूल्यांकन कर समय पर सुधार किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल योजनाओं का संचालन पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके वास्तविक परिणामों का भी मूल्यांकन होना चाहिए। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग केवल उपचार की व्यवस्था तक सीमित न रहे, बल्कि यह भी आकलन करे कि योजनाओं के लागू होने से मरीजों की संख्या, उपचार की गुणवत्ता और लोगों को मिलने वाले लाभ में कितना सुधार हुआ। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में वास्तविक बदलावों को मापते हुए नीतियों में सुधार करने पर जोर दिया।

लाठीचार्ज के विरोध में कल्याण में जनआक्रोश, मोदी-शाह और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

विनय उजाला, कल्याण

कल्याण/दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET परीक्षा में धांधली और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को कल्याण पूर्व में एक विशाल निषेध सभा का आयोजन किया गया।

सभा में सैकड़ों नागरिक, महिलाएं और छात्र शामिल हुए। पूरे पंडाल में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। महिलाओं ने मोदी-शाह सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। छात्रा वैशाली पाटील सहित कई छात्राओं ने कहा कि कम से कम शिक्षा में तो भ्रष्टाचार मत करो। सभा को संबोधित करते हुए नीरज दुबे ने कहा कि बाबासाहेब आंबेडकर ने शिक्षा, संगठित हो और संघर्ष करो का मंत्र दिया था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार



दमनकारी नीति पर चल रही है। पूर्व नगरसेवक उदय रसाल ने कहा, जनरल डायर के बाद देश ने पहला जनरल कायर प्रधानमंत्री देखा है, जिसने अपने ही देश के बच्चों पर लाठी चलाने का आदेश दिया।

सभा में NEET पेपर लीक, छात्रों की आत्महत्या और एक छात्रा की मौत की खबर पर गहरा दुख व्यक्त किया गया। इंकलाब जिंदाबाद और हर हर महादेव के नारों से परिसर गूंज उठा।

सभा में 9 प्रस्ताव पारित किए गए

- जंतर-मंतर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा।
- प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें।
- KG से PG तक पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर शिक्षा सस्ती की जाए।
- पेपर लीक से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजा मिले।
- लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों की जांच हो और कील लगी लाठियां इस्तेमाल करने वालों पर FIR हो।
- घायल छात्रों को मुआवजा दिया जाए।
- छात्राओं से बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए।
- छात्रों पर लगाए गए झूठे केस बिना शर्त वापस हों।
- महाराष्ट्र सहित पूरे देश में आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं।

आयोजकों ने बताया कि इन प्रस्तावों की प्रतियां तहसीलदार और जिलाधिकारी को माननीय संबोधन के साथ, जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बिना माननीय लगाए भेजी जाएंगी, यह भी विरोध का प्रतीक है।

सभा में उदय रसाल, संजय निरभवने, शरद पाटील, नीरज दुबे, सदानंद तिवारी, श्रीनिवास घाणेकर, सुरेश पाटील, मनोज नायर, हेमंत चौधरी, डॉ. प्रकाश कांबळे, समीर वेदपाठक, सौ. वैशाली सोनटक्के, सौ. भावना सुरळके, सौ. मीनाक्षी आहेर, सौ. ज्योती मेश्राम सहित सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। अंत में चेतावनी दी गई कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पनवेल रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई...

39 मामलों में वांछित शातिर चोर गिरफ्तार, 26.31 लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण बरामद

रेनू पांडेय/नवी मुंबई

पनवेल रेलवे पुलिस ने ट्रेन यात्रियों के बैग और कीमतीसामान चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 26 लाख 31 हजार 68 रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए हैं।

जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ मुंबई रेलवे सहित देश के विभिन्न राज्यों में चलती एक्सप्रेस ट्रेनों के एसी कोच में चोरी के 39 मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, 17 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 1 बजे मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस (12617) के पनवेल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचने के बाद एसी कोच से एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में जल्दबाजी में उतरता दिखाई दिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस उपनिरीक्षक एस. एम. पाटील, पुलिस हवलदार सोमनाथ इंगवले और कदम ने उसे रोककर पूछताछ की। उसके बैग की तलाशी लेने पर बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषण मिले। आभूषणों के संबंध में संतोषजनक जवाब न देने पर उसे पनवेल रेलवे पुलिस थाने लाकर विस्तृत पूछताछ की गई।

पुलिस निरीक्षक एन. बी. यमगर, महिला सहायक पुलिस निरीक्षक बी. एन. पुरी तथा पुलिस उपनिरीक्षक एस. डी. यादव की पूछताछ





में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने ट्रेन यात्रियों के बैग चोरी कर ये आभूषण हासिल किए थे। आरोपी की पहचान रघू सुमन खोसला (41 वर्ष), निवासी लोनी देहात, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), मूल निवासी पंजाब के रूप में हुई। जांच में पता चला कि उसके खिलाफ मुंबई रेलवे पुलिस समेत विभिन्न राज्यों में एसी कोच में चोरी के 39 मामले दर्ज हैं। उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के बाद पुलिस ने 18 जुलाई को उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।

बरामद आभूषणों की जानकारी मुंबई रेलवे कंट्रोल रूम के माध्यम से देशभर के रेलवे पुलिस थानों को भेजी गई। इसके बाद कोंकण रेलवे पुलिस, मडगांव (गोवा) ने पुष्टि की कि ये आभूषण उनके यहां दर्ज एक चोरी के मामले से संबंधित हैं। यह मामला नेत्रावती एक्सप्रेस में हुई चोरी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता जेरिल स्कायरिया अपने परिवार के साथ केरल जा रहे थे। यात्रा के दौरान उनकी पत्नी के सिरहाने रखे सोने-चांदी के आभूषण और आईफोन से भरा हैंडबैग अज्ञात चोर लेकर फरार हो गया था। आईफोन की लोकेशन मडगांव रेलवे स्टेशन पर मिलने के बाद कोंकण रेलवे पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को आगे की जांच के लिए कोंकण रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

विठ्ठलवाडी आगार के फेरे बंद

पंढरपुर आषाढ़ी वारी के लिए ठाणे एसटी विभाग तैयार, 168 बसें दौड़ेंगी

विनय उजाला कल्याण

आषाढ़ी एकादशी के पावन पर्व पर पंढरपुर जाने वाले वारकरियों की सुविधा के लिए महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) के ठाणे विभाग ने विशेष परिवहन योजना तैयार की है। वारकरियों की सुखकर और सुरक्षित यात्रा के लिए कुल 303 फेरियों का कोटेवार नियोजन किया गया है। एसटी महामंडल के ठाणे विभाग द्वारा आषाढ़ी एकादशीनिमित्त वारी के लिए विशेष वाहतूक नियोजन किया गया है। ठाणे, कल्याण, विठ्ठलवाडी, भिवंडी, शहापुर, मुरबाड और वाडा इन सभी आगारों से विशेष बसें छोड़ी जाएंगी। वारकरियों को ले जाने के लिए जाते समय 168 बसें और पंढरपुर से वापसी के लिए 135 बसें, ऐसे कुल भव्य पैमाने पर नियोजन किया गया है। ग्रुप बुकिंग, ओआरएस और अतिरिक्त बसों की भी सोय की गई है। ठाणे विभाग के इस नियोजन से कल्याण-डोंबिवली, ठाणे व ग्रामीण भाग के भाविकों को पंढरपुर यात्रा के लिए बड़ी मदद होने वाली है। वारकरियों ने इस सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठाएं, ऐसा आवाहन एसटी प्रशासन ने किया है। पंढरपुर दर्शन के बाद वारकरियों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए परतीच्या प्रवासाचे भी उत्तम नियोजन किया गया है। पंढरपुर यात्रा के लिए बसों का नियोजन होने के कारण विठ्ठलवाडी आगार से इतर भागों के लिए सूचना के अनुसार कुछ नियमित बस फेरे 23 से 27 जुलाई के कालावधी में तात्पुरते स्थगित ठेवण्यात आले हैं। यात्रियों ने इसकी नोंद लेकर सहयोग करें।

रद्द फेरे इस प्रकार

- विठ्ठलवाडी ते नांदाबाद - रात्री 12.10 वा.
- विठ्ठलवाडी ते विटा - सकाळी 10.30 वा.
- विठ्ठलवाडी ते पाथर्डी - सकाळी 8.00 वा.आणि सकाळी 11.30 वा.
- विठ्ठलवाडी ते अहिल्यानगर - सकाळी 05.30 वा.आणि दुपारी 2.30 वा.
- विठ्ठलवाडी ते गोंदवले - सकाळी 06.30 वा.

पनवेल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म विस्तार कार्य के दौरान हादसा, छत का हिस्सा और OHE पोल गिरा

नवी मुंबई/ रेनू पांडे

नवी मुंबई के पनवेल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म विस्तार कार्य के दौरान गुरुवार शाम एक निर्माण संबंधी हादसा हो गया।

पुराने स्टेशन ढांचे को हटाने के दौरान छत की एक पुरानी शीट और ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) सपोर्ट पोल अचानक गिर गया। घटना निर्माण क्षेत्र तक ही सीमित रही और इसमें किसी के घायल होने



की सूचना नहीं है। मुंबई रेल विकास निगम (MRVC) के अनुसार, यह घटना पुराने ढांचे को योजनाबद्ध तरीके से हटाने के दौरान हुई। अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और सभी लोकल व अन्य रेल सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं। फिलहाल निर्माण स्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू कर दिए गए हैं और प्लेटफॉर्म विस्तार का कार्य जारी है।

छात्रों को तनावमुक्त रखने के लिए मॉडर्न कॉलेज ने लॉन्च किया 'कवच हेल्थ कार्ड'



नवी मुंबई/रेनू पांडेय

छात्रों में बढ़ती हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन और तनाव जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के उद्देश्य से मॉडर्न कॉलेज ने विश टू केयर वेलनेस के साथ मिलकर 'कवच हेल्थ कार्ड' लॉन्च किया है। इस पहल के तहत छात्रों की काउंसलिंग करने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य पर भी नजर रखी जाएगी।

'कवच हेल्थ कार्ड' के उद्घाटन समारोह में मॉडर्न कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. शुभदा नायक, डॉ. सुधाकर पाठक, विश टू केयर वेलनेस के सीईओ डॉ. शुभम पाठक, को-सीईओ डॉ. महावीर जैन, डॉ. अश्विनी पांडे, डॉ. नेहा पाठक, डॉ. कपिल पाटिल, डॉ. श्वेता तिवारी, साइकोलॉजिस्ट प्राची मिश्रा, मुनीर शेख सहित कई मान्यवर उपस्थित रहे।

विश टू केयर वेलनेस के सीईओ डॉ. शुभम पाठक ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से छात्रों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जाएगी। साथ ही कॉलेज कैंपस में किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति आने पर छात्रों को तत्काल इमरजेंसी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं, को-सीईओ डॉ. महावीर जैन ने बताया कि 'कवच हेल्थ कार्ड' के माध्यम से छात्रों को दुर्घटना संबंधी सुरक्षा भी प्रदान की गई है। कॉलेज से घर आने-जाने के दौरान किसी दुर्घटना की स्थिति में छात्रों को दो लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल सुरक्षा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को तनावमुक्त वातावरण देने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर एक मजबूत व्यवस्था तैयार करना है।

कल्याण डोंबिवली मनपा का लिपिक 6 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

विनय उजाला कल्याण। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के ब प्रभाग में मालमत्ता कर विभाग के लिपिक सिद्धार्थ रावसाहेब बोराडे (उम्र 49) को एंटी करप्शन ब्यूरो (लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग) की ठाणे इकाई ने मंगलवार शाम संतोषी माता रोड पर एक शिकायतकर्ता से 6 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। मनपा की 30 साल की नौकरी में रिश्वत लेते पकड़ा गया यह 48 वां कर्मचारी है। कल्याण पश्चिम के ब प्रभाग में सिद्धार्थ बोराडे मालमत्ता कर विभाग में प्रभाग हद के मालमत्ताओं का कर लगाने का काम अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में करते हैं। एंटी करप्शन विभाग की शिकायत में कहा गया है कि यात्रिकरणी के शिकायतकर्ता को अपनी सोसाइटी की तलमजले पर खड़ी चार पहिया गाड़ी को वाहनतल पर अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना था। यह काम करवाने के लिए बोराडे ने वाहन मालिक से 10 हजार रुपये की मांग की थी। पैसे मांगे जाने से वाहन मालिक अस्वस्थ हो गया। उसे डर था कि पैसे न देने पर उसका काम नहीं होगा। इस डर से उसने 9 जुलाई को बोराडे के खिलाफ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, ठाणे में शिकायत दर्ज कराई। पथक ने 9 जुलाई को ही शिकायत की सत्यता जांची और जांच में बोराडे द्वारा पैसे मांगे जाने की पुष्टि हुई।

नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी

कल्याण तालुका परिसर में मूसलाधार बारिश

विनय उजाला/टिटवाला

कल्याण शहर सहित डोम्बिवली उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर शहाड, मोहने, टिटवाला और ग्रामीण परिसर में गुरुवार दोपहर बाद मुसलाधार बारिश ने जोरदार हाजिरी लगाई। कुछ ही देर में सड़कों पर बड़े पैमाने पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई और नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

तेज बारिश के कारण कल्याण-उल्हासनगर, अंबरनाथ और टिटवाला के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। दफ्तर छूटने के समय बारिश शुरू होने से घर लौट रहे नागरिकों की भारी भीड़ और अफरा-तफरी देखी गई। कई जगहों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं और ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो गई। मोहने, टिटवाला और ग्रामीण भाग में बारिश का जोर कायम है, नाले और छोटे नदी-नाले उफान पर बहने लगे हैं। लगातार हो रही बारिश से परिसर की नदियों के जलस्तर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसको लेकर प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है।



प्रशासन की अपील

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि खतरनाक जगहों पर न जाएं, नदी-नालों और तेज पानी के बहाव के पास अनावश्यक गर्दी न करें। बाजारपेठ में भी बारिश के कारण कारोबार पर असर पड़ा है, कई जगह पैदल और दोपहिया चालकों को पानी से रास्ता निकालना पड़ा। कुछ भागों में बिजली आपूर्ति भी बाधित होने की जानकारी मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक और मुसलाधार बारिश की संभावना है। नागरिक अत्यावश्यक काम के बिना घर से बाहर न निकलें, मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करें और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। फिलहाल पूरे कल्याण परिसर में बारिश ने जोरदार वापसी की है, जिससे दैनिक जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और प्रशासन पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है।

संक्षिप्त समाचार

बेटी की सर्जरी के लिए जोड़ी पूंजी घर से चोरी, 6 घंटे में दिल्ली पुलिस ने रकम बरामद की

नई दिल्ली। दिल्ली की उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस ने महज 6 घंटे में चोरी के एक मामले को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ़्तार किया है। दिल्ली पुलिस की इस तेज कार्रवाई से एक छह साल की बच्ची की सर्जरी उम्मीद भी जगी है। पुलिस ने बताया कि केशवपुरम थाना क्षेत्र में एक परिवार ने अपनी छह साल की मासूम बेटी की रीढ़ (स्पाइन) की गंभीर सर्जरी के लिए जीवनभर की जमा-पूंजी और गहने बेचकर करीब 12.5 लाख रुपए जुटाए थे, लेकिन इलाज से ठीक पहले चोरों ने घर में सेंध लगाकर वह सब कुछ चुरा लिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, 22 जुलाई को केशव पुरम थाने में एक घर की खिड़की का शीशा तोड़कर चोरी किए जाने के संबंध में शिकायत दी गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ अनजान लोग उनके घर में घुस आए और लगभग 12.5 लाख रुपए की कीमत के गहने चुराकर भाग गए। जांच के दौरान पता चला कि शिकायतकर्ता की 6 साल की बेटी की एम्स में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी का इलाज चल रहा है। इलाज के लिए जरूरी पैसे जुटाने के लिए परिवार ने अपने गहने बेच दिए थे और अपनी जीवन भर की बचत जमा की थी। इसके बाद, केशव पुरम थाने में मामला दर्ज किया गया और प्राथमिकता के आधार पर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक खास टीम बनाई गई और आरोपियों को पकड़ने का काम सौंपा गया। तकनीकी सबूतों और लगातार कोशिशों के आधार पर एक शातिर चोर की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान दिल्ली के वजीरपुर इलाके के 25 वर्षीय अभिषेक उर्फ राजे के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान उसने उस जगह के बारे में बताया जहां उसने चोरी किए गए गहने छिपाकर रखे थे। उनकी जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की। वहां से चोरी हुए गहने और कीमती सामान बरामद करके पीड़ित परिवार को लौटा दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस की तेज कार्रवाई से न सिर्फ चोरी का सामान सफलतापूर्वक बरामद हुआ, बल्कि परिवार की उम्मीद भी वापस आई और यह सुनिश्चित हुआ कि बच्ची का इलाज बिना किसी रुकावट के जारी रह सके।



सीजेपी प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस अलर्ट, 400 से अधिक पाकिस्तानी अकाउंट्स किए ब्लॉक

नई दिल्ली। दिल्ली में चल रहे सीजेपी के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पर कुछ गलत जानकारी साझा करने की कोशिश हो रही है। अभी तक 400 से अधिक पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की गई है, जो मौजूदा स्थिति का फायदा उठाकर गलत और भ्रामक जानकारी शेयर कर रहे हैं। बयान में आगे कहा गया है कि ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सक्रिय थे। उनका मकसद लोगों को भड़काना और छात्रों का ध्यान भटकाना है। दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी गलत, अपुष्ट जानकारी और कंटेंट के बहकावे में न आएं। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले उसे जरूर जांच लें। किसी भी असामाजिक तत्व को भावनाओं का फायदा न उठाने दें। दिल्ली पुलिस ने छात्रों से कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन आपका अधिकार है और पुलिस इसका सम्मान करती है। वहीं, इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुरुवार शाम 4 बजे से जंतर-मंतर के आसपास आठ घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश दिया। मंत्रालय ने मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश जारी करते हुए कहा कि सचिव इस बात से संतुष्ट हैं कि जन-व्यवस्था बनाए रखने और किसी अपराध के लिए उकसावे को रोकने के हित में ऐसा करना जरूरी है। आदेश में निर्देश दिया गया कि जंतर-मंतर के आसपास 1.5 किलोमीटर के दायरे में 23 जुलाई को शाम 4.00 बजे से रात 12.00 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं (सभी तकनीकों पर) बंद रखी जाएं। वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने इस आंदोलन से जुड़े लोगों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि बातचीत जेपी नड्डा के कार्यालय या घर पर, किसी भी सुविधाजनक समय पर हो सकती है और वे स्वयं भी इस चर्चा में शामिल होंगे।



मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर दिल्ली नगर निगम ने कसी कमर

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में मानसून आते ही कई तरह की बीमारियां फैलना शुरू हो जाती है। आज से कई साल पहले जब दिल्ली में डेंगू फैला था, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी थी और कई सारे मरीजों की मौत भी हो गई थी, उसके बाद से हर साल मानसून आते ही डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम कई तरह के अभियान चलाती है। इस बार भी एमसीडी मानसून का मौसम शुरू होने से पहले और मौसम शुरू होने के बाद डेंगू को लेकर गंभीर नजर आ रही है। दिल्ली नगर निगम हर साल कई तरह का अभियान चलाता है। जिसमें मच्छरों से बचाव के लिए पानी में दवा का छिड़काव करना, घरों में पानी जमा होने वाली जगह की नियमित साफ सफाई और पानी जमा होने वाली जगह पर मच्छरों के लारवा खत्म करने के लिए दवा का छिड़काव करना शामिल है। इतना ही नहीं नगर निगम घरों में पानी जमा होने और उसको साफन करने पर लोगों के चालान काटना नोटिस देने की कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता के लिए भी हर गली मोहल्ले में अभियान चलाता है। दिल्ली नगर निगम की टीम जगह जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके साथ ही हर रविवार को अपने घरों के गमले कूलर और अपनी जगह होने वाली जगह की सफाई करने के लिए भी अभियान चलाया जाता है। हाल ही में मानसून से पहले तैयारी के तहत दिल्ली में बड़े स्तर पर फॉगिंग और जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए पूरे शहर के सभी 250 वार्ड में फॉगिंग मशीनों के द्वारा फागिंग की जा रही है। ऑटो रिक्शा के माध्यम से जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। दिल्ली के निगम के सभी सरकारी स्थान में डेंगू की जांच की सुविधा मुख्य उपलब्ध है।



नशामुक्ति के उपायों को सरकार ने किया मजबूत

नई दिल्ली। मादक पदार्थों की मांग में कमी, पुनर्वास और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और सेवाओं की बेहतर डिलीवरी के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन को लगातार मजबूत कर रहा है। मंत्रालय ने निधि जारी करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने, नशामुक्ति के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने और देश भर में पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए उपाय शुरू किए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने सांसद प्रतिमा मंडल द्वारा पूछे गए कई प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। केन्द्रीय मंत्री ने सदन को सूचित किया कि विभाग ने विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत प्रस्तावों के समय पर आगे बढ़ाने और राशि का जारी होना सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त निगरानी तंत्र स्थापित किया है। राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्य योजना (एनएपीडीआर) और अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) जैसी योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले भागीदार गैर सरकारी संगठनों को अनुदान जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी लागू की गई है। इससे दस्तावेजीकरण की आवश्यकता कम होगी और प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा। मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे मे बताते हुए, वर्मा ने कहा कि मंत्रालय मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्य योजना के तहत एक व्यापक और साक्ष्य-आधारित रणनीति लागू कर रहा है। यह रणनीति नई दिल्ली स्थित एम्स के राष्ट्रीय मादक पदार्थ निर्भरता उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी) द्वारा देश में मादक पदार्थों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर किए गए पहले राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर आधारित है।



तकनीक से दिल्ली को स्वच्छ-सुंदर बनाना हमारी प्राथमिकता : रेखा गुप्ता

सीएम ने कचरा उठाने वाली 917 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई

नई दिल्ली, एजेंसी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वेस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके में घर-घर जाकर कचरा उठाने और उसे दूसरी जगह ले जाने (सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन) के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने कचरा उठाने वाली 917 आधुनिक (मॉर्डन) गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई।

इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली (एमसीडी) के सफाई कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने कर्मचारियों की लगन से की गई सेवा की तारीफ की और एक साफ-सुथरी और सुंदर दिल्ली बनाने में उनके अहम योगदान को सराहा।

उन्होंने कर्मचारियों के साथ खाना भी खाया और उनकी निष्ठा और सेवा के लिए उनका आभार जताया। इस मौके पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद और मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही, एमसीडी कमिश्नर संजीव खिरवार और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।





मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का मकसद सिर्फ कचरा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि एक आधुनिक, टेक्नोलॉजी पर आधारित, पारदर्शी और नागरिकों पर केंद्रित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है।

उन्होंने कहा कि इस नए सिस्टम से घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने का काम ज्यादा कुशल, समय पर और जवाबदेह बनेगा, साथ ही यह दिल्ली को साफ-सुथरा, स्वस्थ और सुंदर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

उन्होंने भरोसा जताया कि आधुनिक टेक्नोलॉजी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की भागीदारी से दिल्ली देश की सबसे साफ और सबसे अच्छी तरह से मैनेज की जाने वाली राजधानी बनेगी। एक सरकारी बयान के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट में वेस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 25 वार्डों के लगभग 4.5 लाख परिवार शामिल होंगे।

बयान में कहा गया है कि इसे पहले चरण में छह वार्डों में शुरू किया गया है, जबकि बाकी 19 वार्डों को 31 अगस्त तक इस सिस्टम के दायरे में लाया जाएगा।

साफ-सफाई सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, समय पर और कुशलता से घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने के मकसद से 917 अत्याधुनिक गाड़ियों और कचरा उठाने वाले आधुनिक उपकरणों का बेड़ा तैनात किया गया है।

इस बेड़े में तंग गलियों में आसानी से पहुंचने के लिए 225 ई-रिक्शा, 550 मिनी टिपर, 52 कॉम्पैक्टर, 41 हुक लोडर, 28 टाटा 407 गाड़ियां, 10 डंपर, छह बिन वॉशर, 123 एफसीटीएस बिन और 1,300 लीटर क्षमता वाले 1.1 सीबीएम बिन शामिल हैं। ये आधुनिक संसाधन हर घर से 100 प्रतिशत, समय पर और प्रभावी ढंग से कचरा इकट्ठा करना सुनिश्चित करेंगे।

पेपर लीक विवाद के बीच आईएएस नरेश पाल गंगवार बने उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव

नई दिल्ली, एजेंसी

देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और कथित अनियमितताओं, खासकर नीट से जुड़े विवादों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। नियुक्ति समिति ने राजस्थान कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है।

यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की विश्वसनीयता को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नीट और अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं से जुड़े विवादों के बाद छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों ने परीक्षा प्रणाली की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना शामिल हो सकता है।



केंद्र सरकार का यह फैसला परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही को मजबूत करने और सुधारों की प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नरेश पाल गंगवार राजस्थान कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनके पास करीब तीन दशक का प्रशासनिक अनुभव है। अपनी नई नियुक्ति से पहले वह मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत थे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने से पहले गंगवार ने राजस्थान में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाईं। वह राज्य के कई जिलों में जिला कलेक्टर रहे और राज्य सरकार में प्रमुख सचिव सहित कई अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं। उन्हें वर्ष 2010 से 2014 के बीच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के शुरुआती चरण में राजस्थान की सौर नीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय भी दिया जाता है।

तीन दशक का प्रशासनिक अनुभव

नरेश पाल गंगवार राजस्थान कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनके पास करीब तीन दशक का प्रशासनिक अनुभव है। अपनी नई नियुक्ति से पहले वह मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत थे।

धंसे हुए हिस्से को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया

ख्याला में व्यस्त चौराहे पर अचानक धंसी सड़क, यातायात प्रभावित

नई दिल्ली, एजेंसी

पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके में एक व्यस्त चौराहे पर मुख्य सड़क शुक्रवार तड़के अचानक धंस गई। इस दौरान, ईंटों से भरा एक ट्रक गहरे गड्ढे में फंस गया। गनीमत रही इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

बताया गया कि ख्याला बस स्टैंड के पास शुक्रवार सुबह सड़क अचानक धंसी। उसी समय ईंटों से लदा हुआ एक भारी-भरकम ट्रक गुजर रहा था, जो इस घटना की चपेट में आया। घटना के बाद मार्ग पर आवाजाही रोक दी गई।

इसके बाद ट्रक को वहां से हटाया गया और सुरक्षा के मद्देनजर सड़क के धंसे हुए हिस्से को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया।

हालांकि, जिस तरह घटना हुई, वहां जलभराव जैसी स्थिति नहीं थी। बारिश के पहले ही सड़क धंसने पर एक बड़ा हादसा टल गया। यह गड्ढा ख्याला बस स्टैंड से केशोपुर रोड की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर बना है, जो इलाके का बेहद व्यस्त रास्ता माना जाता है।

इस सड़क से प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन और पैदल यात्री गुजरते हैं। आसपास केशोपुर मंडी, कई स्कूल, मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण संस्थान होने के कारण दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है।



जेएनयू ने छात्रों को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों से दूर रहने की दी सलाह

नई दिल्ली, एजेंसी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने अपने छात्रों और सदस्यों को जंतर-मंतर या उसके आसपास होने वाली सभाओं और विरोध प्रदर्शन में न शामिल होने की सलाह दी है। इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

विश्वविद्यालय ने एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा, जेएनयू समुदाय के सभी सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे जिम्मेदारी से काम लें और अपनी निजी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। सार्वजनिक प्रदर्शनों पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप जंतर-मंतर, नई दिल्ली या उसके आस-पास होने वाली सभाओं में शामिल होने या वहां जाने से बचें।

विश्वविद्यालय ने सोशल मीडिया पर संयम बरतने की सलाह दी है। जेएनयू ने कहा, कृपया सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करें। नियमों का उल्लंघन करने पर लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई और यूनिवर्सिटी की आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आप शैक्षणिक जिम्मेदारी और जिम्मेदार नागरिकता के मूल्यों को बनाए रखें।



दिल्ली विश्वविद्यालय भी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, छात्रों और फैकल्टी सदस्यों, आपकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान दें कि नई दिल्ली जंतर-मंतर पर किसी भी तरह की गैर-कानूनी सभा या प्रदर्शन पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कड़े नियम लागू होने के कारण कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

उत्तर रेलवे ने लोनी रेलवे स्टेशन पर चलाया टिकट चेकिंग अभियान

नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का दिल्ली मंडल बिना टिकट यात्रा और ट्रेनों में अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के प्रयासों के तहत नियमित रूप से टिकट चेकिंग अभियान चलाता है। इन अभियानों के परिणामस्वरूप कई लोगों को बिना टिकट पकड़ा गया और जुर्माना वसूला गया है। ये अभियान इस उद्देश्य से चलाए जाते हैं कि यात्री वैध टिकट के साथ यात्रा करें और ट्रेनों में अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके।

बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री न केवल रेलवे के राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वैध टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के अधिकारों का भी उल्लंघन करते हैं। दिल्ली मंडल ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों का पता लगाने और उन पर जुर्माना लगाने के लिए दिल्ली शाहदरा शामली खंड के लोनी रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले कुल 71 मामले पकड़े गए और 37,210 रुपये का रेलवे राजस्व वसूला गया। दिल्ली के मंडल रेल प्रबंधक पुष्पेश रमण त्रिपाठी ने वैध टिकट के साथ यात्रा करने के महत्व पर जोर दिया और यात्रियों से टिकट चेकिंग स्टाफ का सहयोग करने का आग्रह किया।

पेपर लीक विवाद के बीच नीट परीक्षा के सफल छात्रों ने किया मोदी सरकार का समर्थन

नई दिल्ली, एजेंसी

नीट-यूजी पेपर लीक पर देशभर में विरोध प्रदर्शन के बीच परीक्षा पास करने वाले छात्रों ने केंद्र सरकार का समर्थन किया है। छात्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके (पेपर लीक) लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं। पहली बार नीट परीक्षा में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

कर्नाटक के हुबली की छात्रा दानेश्वरी सलीमत ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, मैंने नीट परीक्षा पास की और अच्छी रैंक हासिल की। अब नीट परीक्षा में कोई समस्या नहीं है। पहली नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या हुई थी, लेकिन अब आयोजित दूसरी परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है और अच्छा कोर्स मिलने की संभावना है।

छात्रा ने कहा, कुछ लोग नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध कर रहे हैं। नीट बोर्ड और केंद्र सरकार ने एडमिशन के लिए काउंसलिंग बुलाई है। हम काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं। हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। पहली बार नीट परीक्षा में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।





छात्रा दानेश्वरी सलीमत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लोग, जिनमें विपक्षी पार्टियां भी शामिल हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। यह सच से बहुत दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं।

छात्र प्रभात ने कहा, मैंने इस साल नीट की परीक्षा दी। मुझे 39 अंक मिले। सरकार का फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन का फैसला काफी अच्छा है। बहुत से छात्रों का नीट परीक्षा का सपना रहता है, जिसके लिए वे अपनी तैयारी शुरू करते हैं। छात्र नीट परीक्षा के लिए दो-तीन साल की तैयारी करते हैं। इसके बाद फल नहीं मिलता है तो वह डिप्रेशन में चला जाता है। फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन के बाद पेपर लीक के मामलों में जल्द सजा हो सकेगी और भविष्य की परीक्षाएं भी सही ढंग से हो सकेंगी।

डब्ल्यूएचओ ने 'प्रोटेक्ट' नाम से सात प्रमुख उपायों का एक पैकेज तैयार किया है

हर साल डूबने से 3 लाख मौतें, डब्ल्यूएचओ ने बताए जान बचाने के 7 असरदार उपाय

नई दिल्ली, एजेंसी

हर साल दुनिया भर में करीब तीन लाख लोग डूबने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या बच्चों की होती है। आज भी 5 से 14 साल के बच्चों की मौत की सबसे बड़ी वजहों में डूबने से होने वाली मौतें शामिल हैं।

इन चिंताजनक आंकड़ों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 25 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मनाए जाने वाले डूबने से बचाव दिवस से पहले एक नया तकनीकी पैकेज लॉन्च किया है। इसका मकसद सरकारों और समुदायों को ऐसे आसान और असरदार उपाय बताना है, जिनसे डूबने से होने वाली मौतों को काफी हद तक रोका जा सके।



डब्ल्यूएचओ का कहना है कि डूबने की ज्यादातर घटनाएं नदियों, तालाबों, झीलों, कुओं, घरों में पानी के बड़े भंडार और स्विमिंग पूलों में होती हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं, जहां दुनिया की 9 प्रतिशत से ज्यादा डूबने की घटनाएं होती हैं।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा कि हर डूबने की घटना एक त्रासदी है और राहत की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर को रोका जा सकता है।

उनका कहना है कि इसके लिए सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, बल्कि शिक्षा, परिवहन, आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन समेत सभी को मिलकर काम करना होगा।

इसी सोच के साथ डब्ल्यूएचओ ने प्रोटेक्ट नाम से सात प्रमुख उपायों का एक पैकेज तैयार किया है।

पहला उपाय है पानी के आसपास सुरक्षित बुनियादी ढांचा तैयार करना, ताकि लोग गलती से पानी में न गिरें। दूसरा, हादसे की स्थिति में तुरंत बचाव और प्राथमिक उपचार यानी रेस्क्यू और सीपीआर जैसी सुविधाओं को मजबूत करना। तीसरा, उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जो रोजगार के लिए पानी के आसपास काम करते हैं, जैसे मछुआरे या नाविक।

निम्न-मध्यम आय वाले देश अधिक प्रभावित

डब्ल्यूएचओ का कहना है कि डूबने की ज्यादातर घटनाएं नदियों, तालाबों, झीलों, कुओं, घरों में पानी के बड़े भंडार और स्विमिंग पूलों में होती हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं, जहां दुनिया की 90 प्रतिशत से ज्यादा डूबने की घटनाएं होती हैं।

सम्पादकीय

नीट पेपर लीक के बाद उठे सवाल : क्या सिर्फ आश्वासन से लौटेगा युवाओं का भरोसा?

किसी भी मसले पर सरकार के रुख की वजह से अगर जनता या उसके एक हिस्से के बीच असंतोष फैलता है, तो उसका हल निकालना सरकार का ही दायित्व है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए अगर यह कहा कि प्रश्नपत्र लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार ने त्वरित अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, तो यह वक्त का तकाजा है। मगर सदिच्छाओं से ही अगर समस्याओं का समाधान निकल पाता, तो आज देश में बड़ी तादाद में युवाओं के सामने शायद सड़क पर उतरने की नौबत नहीं आती। निश्चित तौर पर नीट 2026 के प्रश्नपत्र लीक होने और इसकी वजह से समूची परीक्षा का रद्द होना विद्यार्थियों के बीच असंतोष भड़कने का तात्कालिक कारण बना है, लेकिन सवाल है कि क्या यह प्रश्नपत्र लीक होने का कोई पहला मामला था! ऐसा क्यों है कि देश भर में इससे उपजे आंदोलन और उसमें पुलिस कार्रवाई के रुख को लेकर तीखे सवाल उठे हैं और इसके बावजूद सरकार को किसी की जिम्मेदारी तय करना जरूरी नहीं लगता। प्रदर्शनकारियों की एक बुनियादी मांग है कि इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार की नजर में इस सवाल की कोई अहमियत नहीं है। वरना क्या वजह है कि इस मुद्दे पर देश के अन्य हिस्सों में भी आंदोलन का दायरा फैलने के बावजूद सरकार अब तक कोई ठोस कार्रवाई करती नहीं दिखी है। यह एक बड़ा कारण हो सकता है कि विद्यार्थियों के एक बड़े तबके के बीच सरकार की कथनी पर भरोसा नहीं बन पा रहा है। च यह है कि पिछले कई वर्षों से अक्सर किसी न किसी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले सामने आते रहे और अगर किसी घटना ने तूल पकड़ लिया, तो सरकार की ओर से सबसे पहली कार्रवाई परीक्षा को रद्द करने की हुई। मगर न तो परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी को कठघरे में खड़ा किया गया, न ही संबंधित महकमे के मंत्री से जवाब-तलब किया गया। विपक्ष के एक आरोप के मुताबिक, वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सत्ता में आने के बाद से अब तक 152 प्रश्नपत्र लीक हो चुके हैं और इससे करीब साढ़े सात करोड़ विद्यार्थी प्रभावित हुए। ऐसे में अगर प्रदर्शनकारियों से लेकर विपक्षी दलों की ओर से भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो यह अनायास नहीं है। नीट 2026 के प्रश्नपत्र लीक होने के बाद अब यह मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि सरकार को कई स्तर पर स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ रही है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसा लगता है कि पहले के प्रश्नपत्र लीक के मामलों की अनदेखी से जमा हुआ क्षोभ इस बार फूट पड़ा है। ऐसे में होना यह चाहिए कि सरकार की ओर से भविष्य में सब कुछ ठीक करने की सिर्फ सदिच्छा जताने के बजाय उच्च स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के जरिए स्पष्ट संदेश दिया जाए, ताकि देश के युवाओं के बीच भरोसा पैदा हो। अगर आंदोलन की शुरुआत में ही सरकार ने गंभीरता दिखाई होती और प्रदर्शनकारियों से संवाद किया होता, तो शायद मामला इतना जटिल शक्ल नहीं अख्तियार करता।

सुविचार

भाग्य के भरोसे क्यों रहना,
क्योंकि भाग्य भी तो कर्म के भरोसे है।
-तपन जिंदल, इंदौर

जिंदगी एक नदी के समान है, जो कभी रुकती नहीं
बस जीवन के रास्ते बदलती रहती है।
- डॉ. विनय दीवान, भोपाल

वक्त और विश्वास दोनों अनमोल है,
एक चला जाए तो लौटती नहीं,
दूसरा टूट जाए, तो जुड़ता नहीं।
- डॉ. रमेश जैन, उज्जैन

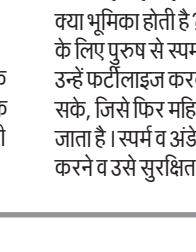
सन्नाटा भी, कुछ ज़िक्र करता हैं,
बस सुनने को, एक बेचैन दिल चाहिए...!
- सुनील लोढ़ा, उदयपुर

संबंध इरादे और विश्वास इतने कमजोर नहीं होने चाहिए
कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं।
- विनोद पाण्डेय, इंदौर

फूलों के गिरने से कभी पेड़ परेशान नहीं होता,
वो हमेशा नए फूलों को खिलाने और
उनके निर्माण में ही लगा रहता है।
- अशोक परमार आष्टा, सीहोर

ज्ञान चुनो, बवाल नहीं...!

'कलम' पकड़ो, मशाल नहीं, ज्ञान चुनो, बवाल नहीं,
तुमसे कल का सूरज है, तुम 'राजनीतिक ढाल' नहीं।
सत्ता हो या फिर विपक्ष, दोनों ही करें विचार-विमर्श,
छात्र केवल मोहरा बनें, यह लोकतंत्र का नहीं है हर्ष।
कक्षा की चौखट-ग्रंथ का मान, ये भारत की पहचान,
प्रश्न उठाना अधिकार हैं, न बने वह नफ़रत की तान।
पेपर लीक हो, शिक्षा पीर, उस पर हो गंभीर तदबीर,
वाद-विवाद हो तथ्य सहित, नहीं हो नारों की लकीर।
युवा शक्ति राष्ट्र की आस, उनमें बसें भविष्य प्रकाश,
राजनीति यदि करनी है, पहले सीखो 'सेवा' विश्वास।
न बनों किसी का हथियार, देश का वे सच्चा आधार,
ज्ञान, विवेक, सत्य के पथ पे, ये हर पीढ़ी के संस्कार।



दैनिक विनय उजाला
- संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इन्दौर-452011 (मध्य प्रदेश)

विशेष सम-सामयिक

शंकराचार्य से लेकर फ़िल्मी हस्तियां व देश के प्रमुख खिलाड़ी भी उनसे यही अपील कर रहे थे। इसलिए यह भी मुमकिन है कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया हो, विशेषकर अपने परिवार के कहने पर। वैसे इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि वांगचुक पर सरकार ने अपनी तरह से कोई दबाव बनाया हो, जैसा कि सरकारें अक्सर किया करती हैं।

सोनम वांगचुक ने खत्म किया अनशन

अब सीजेपी आंदोलन का क्या होगा?



दैनिक विनय उजाला
- नौशाबा परवीन
(लेखिका सम-सामयिक विषयों की टिप्पणीकार हैं)
इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर



एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 23 जुलाई 2026 की देर रात 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। 59-वर्षीय वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के समर्थन में भूख हड़ताल शुरु की थी, जिसके युवा सदस्य केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की भी मांग कर रहे हैं। एक्स पर अपनी पोस्ट में वांगचुक, जो 'सोनम सर' के नाम से अधिक विख्यात हैं, ने कहा कि 'विभिन्न शर्तों पर लम्बी वार्ता' और साथ ही 'देश में आशंकित हिंसा' को रोकने के लिए वह अपनी भूख हड़ताल खत्म कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वह 11 किलो वज़न खोने के बाद 'अब भी जिंदा' हैं। वह नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे, जहां से उन्हें 18 जुलाई 2026 को जबरन उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा, हम चिंतामुक्त और एहसानमंद हैं कि सोनम सर ने 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा, कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन उस समय तक जारी रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं हो जाता।

गौरतलब है कि नीट-यूजी का मई 2026 में पेपर लीक हुआ था। यही पेपर 2024 में भी लीक हुआ था, जिसका मास्टरमाइंड बिहार का संजीव मुखिया बताया गया था, जो 11 माह तक फरार रहा, फिर जब गिरफ्तार किया गया तो तीन माह तक उसके खिलाफ़ अदालत में आरोप-पत्र ही नहीं दाखिल किया गया, जिससे उसे ज़मानत मिल गई और अब सीबीआई का कहना है कि उसके खिलाफ़ कोई आरोप बनता ही नहीं है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पेपर लीक केस फ़ास्ट-ट्रैक अदालतों में चलाये जायेंगे। जब सही से जांच नहीं होगी तो फ़ास्ट-ट्रैक अदालतें ही क्या करेंगी? निरंतर पेपर लीकों की एक लम्बी सूची है, जिनमें कोई जवाबदेही स्थापित नहीं की गई है। मध्य प्रदेश के 2013 व्यापम (व्यवसायिक परीक्षा मंडल) घोटाले में तो राजनेताओं, अधिकारियों और बिचैलियों ने रिश्वत लेकर मेडिकल व इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं तथा सरकारी नौकरियों में भारी धांधली की थी, योग्य छात्रों के स्थान पर डमी उम्मीदवार बैठाए और ओएमआर शीट में हेरफेर की। हज़ारों करोड़ रूपये के इस घोटाले से जुड़े 30 से ज्यादा गवाहों, आरोपियों व संदिग्ध व्यक्तियों की रहस्यमय और अप्राकृतिक परिस्थितियों में मौतें भी हुईं, जिससे देशभर में सनसनी फैली। लेकिन हुआ क्या? जांच और अदालती प्रक्रिया अभी भी जारी है; बस पटवारी भर्ती परीक्षा-2008 में दिसम्बर 2025 में सीबीआई विशेष अदालत, इंदौर ने 10 लोगों को 5-5 साल के कारावास की सज़ा अवश्य सुनायी है। लेकिन पेपर लीक और परीक्षा व भर्ती से संबंधित घोटाले जारी रहे।

दरअसल, वांगचुक ने सीजेपी के 20 जून 2026 से चल रहे आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल की थी, जिसकी मुख्य मांगें हैं कि पेपर लीक की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को भंग किया जाये, जिन 21 छात्रों ने पेपर लीक के कारण आत्महत्या की है, उनके परिवारों को उचित मुआवज़ा दिया जाये और जो लोग परीक्षाओं में अनियमितताओं के लिए ज़िम्मेदार हैं, उनके खिलाफ़ कड़ी क़ानूनी कार्यवाही की जाये। क्या सरकार ने इन मांगों को मान लिया है जो वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है? वांगचुक से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पताल में मुलाक़ात की और चंद चीज़ों का आश्वासन दिया। मांगें मानने और आश्वासन देने में अंतर होता है। वैसे वांगचुक के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए समाज के सभी वर्गों की महत्वपूर्ण शख्सियतों ने वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। हालांकि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सरकार ने विपक्ष के नेताओं को तो वांगचुक से मिलने नहीं दिया। लेकिन 23 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा व डा. जितेंद्र सिंह उनसे मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि परीक्षा सुधारों और पेपर लीक पर जवाबदेही की जो छात्रों की मांगें हैं उन्हें संबोधित किया जायेगा।

सरकार ने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि जिन युवाओं व छात्रों ने 20 जुलाई 2026 को संसद मार्च में हिस्सा लिया था या जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया उनके खिलाफ़ मामले दर्ज नहीं होंगे। लेकिन इस बारे में कोई बात सामने नहीं आयी कि जिन पुलिसकर्मियों व सादे कपड़ों में रहस्यमय व्यक्तियों ने कील लगी लाठियां निहत्थे छात्रों पर बरसायीं और छात्राओं के कपड़े फाड़े व उनके प्राइवेट पार्ट्स पर लाठी मारी, जिससे 100 से अधिक छात्र अस्पताल पहुंचे तो उनके खिलाफ़ क्या कार्यवाही होगी? प्रदर्शन स्थल पर पत्थरों से भरा ट्रक कौन और क्यों लाया था? कहने का अर्थ यह है कि छात्रों की जो मुख्य मांगें हैं उन पर सरकार ने न कोई वायदा किया है और न ही कोई आश्वासन दिया है। इसलिए यह प्रश्न प्रासंगिक है कि वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल क्यों समाप्त की। इसके कुछ मुख्य कारण ये प्रतीत होते हैं- वांगचुक शांतिप्रिय व्यक्ति हैं, उनको डर था कि कहीं पूरे देश में अशांति व हिंसा न फैल जाये। इसलिए उन्होंने जनता से सतर्क व शांतिपूर्ण रहने की अपील भी की। दूसरा यह कि वांगचुक की सेहत निरंतर बद से बदतर होती जा रही थी। प्रधानमंत्री सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने व अपनी सेहत को प्राथमिकता देने का आग्रह किया था।

शंकराचार्य से लेकर फ़िल्मी हस्तियां व देश के प्रमुख खिलाड़ी भी उनसे यही अपील कर रहे थे। इसलिए यह भी मुमकिन है कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया हो, विशेषकर अपने परिवार के कहने पर। वैसे इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि वांगचुक पर सरकार ने अपनी तरह से कोई दबाव बनाया हो, जैसा कि सरकारें अक्सर किया करती हैं। वांगचुक को पहले भी एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) के तहत जेल भेजा जा चुका है। हाल ही में जिलाधिकारी, लेह का 28 फरवरी 2007 का एक पत्र भी वायरल किया गया, जिसमें अन्य बातों के अतरिक्त यह भी कहा गया है- आप (वांगचुक) के चीन व अन्य जगहों पर राष्ट्रविरोधी संपर्क हैं, जिनका राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए शोषण किया गया है या किया जा सकता है। हालांकि यह पत्र न तो कोई न्यायिक निर्णय था व न ही इसमें कोई साक्ष्य दिये गये थे और न ही इस पर कोई क़ानूनी कार्यवाही की गई। लेकिन इसको वायरल करके वांगचुक की छवि पर उंगलियां उठाने का अवसर तो प्रदान ही किया जा सकता था व इससे उन पर पर्याप्त दबाव भी बनाया जा सकता था। बहरहाल, इस पृष्ठभूमि में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अब सीजेपी आंदोलन का क्या होगा? इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि भारत में छात्रों के कुछ आंदोलनों का ज़बरदस्त प्रभाव हुआ है, जैसे 1974-75 में जेपी का आंदोलन जिससे नितीश कुमार, लालू प्रसाद यादव आदि नेता निकले और आपातकाल के बाद 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़ा। लेकिन कुछ छात्र आंदोलन फुस्स होकर भी रह गये। वैसे अगर सीजेपी की वजह से वास्तविक बदलाव नहीं भी आता है तो भी उसने एक सख्त संदेश दे दिया है दृ भारत में जेन-ज़ी की कुंठाओं का प्रबंधन करना सबसे कठिन राजनीतिक चुनौती होगी।

तन्हाई

तनहाई में हम
अकेले होते हैं
तो क्या हम सच में
अकेले होते हैं?
तन्हाई में यादों के मेले
बड़े लम्बे होते हैं
तन्हाई में यादो की चाल
बड़ी मतवाली होती है
अच्छी यादों का पुष्पगुच्छ
और वो महकती यादें
अपनों की यादें,
वो मस्ती की यादें
सहयोग की यादें
वो प्रेम की यादें
यादें तो सिर्फ...
यादें होती है,
बस यूं ही कभी भी
चली आती हैं।
सच्ची... ये हमारा
हिस्सा ही तो होती हैं।
तन्हाई और यादें...
बहुत अच्छे मित्र है
जो हमेशा.....
साथ निभाते है।
तन्हाई में हम कभी
अकेले नही होते
यादें हमारे.....
साथ होती है।
उन यादों में हम अपनों
के बहुत करीब होते हैं।
तन्हाई में वो प्यारी
महकती यादें
तन्हाई में हम अकेले
कहाँ होते हैं
तन्हाई में हम
अपनों की
यादों के बहुत....
करीब होते हैं
जो हमारे दिल के
करीब होते हैं।
उनकी महकती.....
यादें होती हैं।
तो, तन्हाई में हम
अकेले कहां नहीं होते
तन्हाई में यादों के
मेले होते हैं।



दैनिक विनय उजाला
- चंद्रकांति आर्य

मानसून पर मौन, आस्था पर आघात और सत्ता से सवाल

लोकतंत्र केवल बहस का मंच नहीं, भविष्य बचाने का संकल्प भी है

मानसून सत्र शुरू हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में संसद और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। लोकतंत्र के इन सर्वोच्च मंदिरों से देश की जनता को उम्मीद रहती है कि उसके वर्तमान की पीड़ा और भविष्य की चिंता पर गंभीर मंथन होगा। किंतु विडंबना यह है कि जिस मानसून के नाम पर यह सत्र आयोजित है, उसी मानसून से उपजे राष्ट्रीय संकट पर व्यापक चर्चा कहीं दिखाई नहीं देती।

देश का एक भाग सूखे की मार झेल रहा है तो दूसरा भाग बाढ़ की विभीषिका में डूबा हुआ है। कहीं किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठा है तो कहीं उसकी महीनों की मेहनत पानी में बह गई है। शहर जलमग्न हैं, गाँव तबाह हैं, सड़कें टूट रही हैं, पुल बह रहे हैं और हर वर्ष हजारों करोड़ रुपये की राष्ट्रीय संपत्ति प्रकृति के प्रकोप में नष्ट हो रही है। यह केवल मौसम की मार नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही नीतिगत लापरवाही और दूरदृष्टि के अभाव का भी परिणाम है। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का विषय नहीं रहा, वह हमारे वर्तमान का कठोर सत्य बन चुका है। ऐसे समय में संसद और विधानसभाओं का पहला दायित्व होना चाहिए कि वे जल संरक्षण, नदी प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, शहरी नियोजन, वन संरक्षण, आपदा प्रबंधन और किसानों की सुरक्षा पर ठोस राष्ट्रीय नीति तैयार करें। यदि आज भी राजनीतिक शोर, जनहित की आवाज़ को दबा देगा, तो इतिहास यह प्रश्न अवश्य पूछेगा कि जब संकट सामने था तब सत्ता क्या कर रही थी ...?

इसी बीच एक ऐसी घटना सामने आती है जो केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि समाज की आत्मा को झकझोर देती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा समर्पित दान की चोरी हो जाती है और आरोप उसी व्यक्ति पर लगता है, जिसे सेवा और संरक्षण का दायित्व सौंपा गया था। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब सेवा का व्रत स्वार्थ में बदल जाए, तब केवल धन की चोरी नहीं होती विश्वास की भी चोरी होती है।

मंदिरों की पवित्रता केवल पूजा-पाठ से नहीं, बल्कि ईमानदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से बनी रहती है। श्रद्धालु अपने परिश्रम की कमाई भगवान के चरणों में इसलिए समर्पित करता है कि उसका सदुपयोग धर्म और समाज की सेवा में हो। यदि उस विश्वास पर आघात होगा तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। दोषी कोई भी हो, कानून का न्याय समान और निष्पक्ष होना चाहिए। आज आवश्यकता केवल शासन चलाने की नहीं, बल्कि राष्ट्र को दिशा देने की है। सत्ता का वास्तविक धर्म कुर्सी बचाना नहीं, बल्कि जनता का विश्वास बचाना है। धर्म का वास्तविक स्वरूप दिखावा नहीं, बल्कि सत्य, सेवा और मर्यादा है। और लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल बहुमत में नहीं, बल्कि जनहित के प्रति ईमानदार संकल्प में निहित है।

समय आ गया है कि संसद और विधानसभाएँ केवल राजनीतिक संघर्ष का अखाड़ा न बनें, बल्कि भविष्य निर्माण का केंद्र बनें। देश को ऐसी नीतियाँ चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को जल संकट, प्राकृतिक आपदाओं और नैतिक पतन से बचा सकें। देश को ऐसे जनप्रतिनिधि चाहिए जो सत्ता से पहले समाज और स्वार्थ से पहले राष्ट्र को रखें।

आज प्रश्न किसी दल, किसी सरकार या किसी व्यक्ति का नहीं है। प्रश्न भारत के भविष्य का है। यदि आज भी हम नहीं चेते, तो प्रकृति अपना हिसाब भी लेगी और इतिहास अपना फैसला भी सुनाएगा। सत्ता बदलने से राष्ट्र नहीं बदलता, सोच बदलने से राष्ट्र बदलता है। समय की यही पुकार है, राजधर्म निभाइए, धर्म की मर्यादा बचाइए और प्रकृति के साथ न्याय कीजिए। यही भारत की समृद्धि, सुरक्षा और सनातन संस्कृति की सच्ची सेवा होगी।



दैनिक विनय उजाला
-सुरेन्द्र मिश्रा
वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल

विश्व भ्रूण दिवस पर विशेष

दुनिया का पहला परखनली शिशु लुई ब्राउन जिसने संतानहीन दंपत्तियों को दी, उम्मीदों की किरणें



दैनिक विनय उजाला
- वीना गौतम
(लेखिका विशिष्ट मीडिया एवं शोध संस्थान, इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर में कार्यकारी संपादक हैं)
-इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर

जब 25 जुलाई 1978 को लुई ब्राउन के रूप में दुनिया के पहले परखनली शिशु ने जन्म लिया, तो पूरी दुनिया में असंख्य संतानहीन जोड़ों को उम्मीद की किरण नजर आने लगी कि अब उनके आंगन में भी बच्चे की किलकारियां सुनाई देने लगेंगी। इसलिए हर साल 25 जुलाई को विश्व भ्रूणिकी दिवस या 'वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजी डे' के रूप में मनाया जाता है। लुई ब्राउन के आगमन के बाद ही एम्ब्रियोलॉजी शब्द अस्तित्व में आया था। बहरहाल 1978 की सफलता ने माता-पिता बनने के सुख के अनेक रास्ते खोल दिए हैं। आज जहां बिना जैविक सम्पर्कों के भी परिवार आरंभ करने का अवसर मौजूद है, वहीं एचआईवी पॉजीटिव दम्पति भी ऐसी संतान को जन्म दे सकते हैं, जो एचआईवी से पूर्णत: मुक्त हो। इसकी भौतिक पुष्टि भी हो चुकी है। जब जुलाई 2014 में जोहांसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) के उत्तरी उपनगर स्थित विटकोप्पेन हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर के सेफर कंसेप्शन क्लीनिक में 34 वर्षीय थुबेलिह्ले न्दलोवु व उनके पार्टनर गुडविल, जो कि दोनों एचआईवी पॉजीटिव थे, ने जिस बच्चे ज़िकोंडिसो को जन्म दिया, वह एचआईवी निगेटिव था। इस क्लीनिक में एचआईवी पीड़ित यह पहला जोड़ा था, जिसने बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन 1990 के दशक के शुरुआत में ही अलग-अलग देशों में एंटीरेट्रोवायरल दवाओं (एआरटी), वीर्य धुलाई (स्पर्म वॉशिंग) तथा दूसरी सहायक प्रजनन तकनीकों के माध्यम से इस तरह के कई सफल मामलों की शुरुआत होने लगी थी। हालांकि अधिकृत रूप से पूरी तरह एचआईवी निगेटिव पहले शिशु के रूप में ज़िकोंडिसो का ही नाम दर्ज है।

बहरहाल, इनविट्रो फर्टीलाइजेशन या आईवीएफ के लिए जो डॉक्टरों की टीम में गायनेकोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आदि होते हैं, उनमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक महत्वपूर्ण सदस्य होता है, यह अलग बात है कि वह अकसर पर्दे के पीछे ही रहता है। सवाल है इस सबमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट की क्या भूमिका होती है? दरअसल, परखनली शिशु को जन्म देने के लिए पुरुष से स्पर्म व महिला से अंडे एकत्र किए जाते हैं ताकि उन्हें फर्टीलाइज करके एम्ब्रियो या भ्रूण का विकास किया जा सके, जिसे फिर महिला के गर्भाशय में पलने के लिए रख दिया जाता है। स्पर्म व अंडे को एकत्र करने के बाद एम्ब्रियो विकसित करने व उसे सुरक्षित रखने का काम एम्ब्रियोलॉजिस्ट का होता है। साथ ही वह एम्ब्रियो को भविष्य में इस्तेमाल के लिए भी सुरक्षित रखने के अलावा नैतिक मुद्दों को भी संज्ञान में रखता है। जिस पुरुष व महिला ने अपना स्पर्म व अंडा दिया है, उनके दिमाग में यह शंका स्वभाविक है कि प्रजनन प्रक्रिया में वास्तव में उनके ही अंशों का प्रयोग हो रहा है या नहीं। यह एक महत्वपूर्ण नैतिक समस्या है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णत: एम्ब्रियोलॉजिस्ट पर ही होती है, उस पर ही विश्वास करना होता है कि वास्तव में संतान आपकी ही है। लेकिन इससे भी कठिन काम एम्ब्रियोलॉजिस्ट का यह है कि वीर्य में से सक्रिय शुक्राणु (मोटाइल स्पर्म) को असक्रिय शुक्राणु (इममोटाइल स्पर्म) से अलग किया जाए और सामान्य दिखाई देने वाले स्वस्थ्य व तैरने वाले शुक्राणुओं का चयन किया जाए। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है; क्योंकि आधुनिक जीवनशैली, रसायनों के इस्तेमाल, इलैक्ट्रोमेग्नेटिक तरंगें, कैफीन, निकोटीन आदि के एक्सपोजर के कारण सभी सक्रिय शुक्राणुओं में स्वस्थ्य डीएनए नहीं होता।



आज देश-विदेश में ऐसे केंद्र खुल गए हैं जहां कृत्रिम तरीके से गर्भाधारण में सहयोग करने की व्यवस्था है। लेकिन उक्त कारणों को मद्देनजर रखते हुए आवश्यक है कि जो जोड़े आईवीएफ के जरिए संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, वह ऐसी आईवीएफ टीम का चयन करें, जिसमें योग्य एम्ब्रियोलॉजिस्ट शामिल हों और जो उच्च नैतिक स्तर सुनिश्चित करते हों। अगर एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पास मेडिसन में भी डिग्री है तो उसके भी अपने लाभ हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जटिल मामलों में मेडिकल पृष्ठभूमि वाला एम्ब्रियोलॉजिस्ट समस्या उत्पन्न करने वाले कारण का निवारण कर सकता है, जो बहुत से मामलों में रोग की आशंका के कारण होता है। इसके अलावा न दिखाने वाले चिन्ह व लक्षणों के कारण से भी, ऐसा हो सकता है, जिससे अकसर आईवीएफ के नतीजे पॉजीटिव नहीं होते। संक्षेप में बात सिर्फ इतनी सी है कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट उन शुक्राणु व अंडों पर कार्य करते हैं, जो उन्हें प्राप्त होते हैं। अगर वह अच्छे नहीं होंगे तो नतीजा भी अच्छा नहीं होगा।

बहरहाल, अच्छे शुक्राणु व अंडों के लिए आईवीएफ के जरिए संतान प्राप्ति का चयन करने वाले जोड़ों के लिए आवश्यक है कि वह निम्न तथ्यों के विषय में भी सचेत रहें-

- धूम्रपान व शराब से बचें। शराब से स्पर्म काउंट कम हो जाता है और महिलाओं में जन्मजात विकृतियों का खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान से प्रजनन क्षमता कम होती है।
- आदर्श बीएमआई (बॉडी मास इंडेक्स) बनाए रखें। पुरुषों में अतिरिक्त फैट कम स्पर्म काउंट का महत्वपूर्ण कारण है। नियमित एक्सरसाइज से फैट बर्न होता है, हार्मोन स्तर पर तनाव के हानिकारक प्रभाव कम होते हैं और पुरुषों में टेस्टोस्ट्रोन का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन महिलाओं में अत्याधिक एक्सरसाइज अनियमित मासिक चक्र का कारण बन सकती है।
- स्वस्थ्य व संतुलित आहार लेने से हार्मोन का स्तर सामान्य रहता है और प्रजनन सिस्टम के स्वास्थ्य में सुधार आता है। विटामिन सी व ई और जिंक व सिलेनियम से स्पर्म काउंट, शुक्राणुओं की सक्रियता में वृद्धि होती है और महिलाओं के प्रजनन अंगों पर तनाव में कमी आती है। हरी पत्तेदार सब्जियों, अंडे व डेरी उत्पाद, नट्स व सीड्स और रसदार फल में आवश्यक पौष्टिक तत्व जैसे फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन ई व सी आदि प्रदान करते हैं।
- चाय व कॉफी में मिलने वाली कैफीन और चॉकलेट व सॉफ्ट ड्रिंक के सेवन की मात्रा को कम करें।
- साइकिल की सीट सख्त न हो और गर्म स्नान से बचें। अधिक गर्मी से स्पर्म काउंट कम हो जाता है, इसलिए सोना, हॉट बाथ, सन बाथ और टाइट अंडरवियर न पहनें। सख्त सीट पर बैठकर लंबे समय तक साईकिलिंग करने से गुप्त अंगों की नर्व व रक्त धमनियों को नुकसान पहुंचता है।
- नींद की कमी पुरुषों व महिलाओं में हार्मोन स्तर को प्रभावित करती है, इसलिए आठ घंटे की नींद लेना सुनिश्चित करें। साथ ही कोई भी दवा या हर्बल उपचार लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें।

भाजपा ने विपक्ष से की अपील

संसद में चर्चा करें, सड़क पर राजनीति नहीं...

नई दिल्ली, एजेंसी

नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बार-बार अपना रुख बदल रहा है और चर्चा से बचने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि छात्रों के भविष्य पर राजनीति करने के बजाय संसद में चर्चा करें।





गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं को समझती है। देश के युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है और उनसे जुड़े हर मुद्दे पर सकारात्मक पहल करने के लिए तैयार है। शेखावत ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक फायदे का जरिया न बनाए और संसद में आकर खुलकर चर्चा करे। उन्होंने छात्रों को भी सतर्क रहने की सलाह दी और कहा कि कुछ लोग छात्रों की भावनाओं का इस्तेमाल कर अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं और जानते हैं कि किस तरह कुछ लोग आंदोलनों को राजनीतिक दिशा देने का प्रयास करते हैं। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आएं और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें।

पुरानी है पेपर लीक की समस्या : जोशी

इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपर लीक की समस्या केवल आज की नहीं है बल्कि पहले भी कई राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। उन्होंने कहा कि जब पिछली सरकारों के समय ऐसी घटनाएं हुईं, तब क्या जिम्मेदारी तय की गई थी जबकि वर्तमान सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाया है और अब दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वह संसद में आएं, चर्चा करें और मिलकर ऐसा सिस्टम तैयार करने पर विचार करें जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ तेजी से सुनवाई होगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

राहुल चर्चा से भाग रहे : प्रसाद

रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह संसद में चर्चा से बच रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर समाधान निकालने के बजाय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि संसद चर्चा का मंच है और लोकतंत्र में हर मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की जनता सब देख रही है। रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी नेताओं पर आंदोलन की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ नेता हर मुद्दे पर आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुनाव में जनता उन्हें जवाब देती है। उन्होंने कहा कि छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय सभी दलों को मिलकर समाधान तलाशना चाहिए।

वहीं, भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपर लीक एक पुरानी और गंभीर समस्या है, जिसका समाधान दलीय राजनीति से ऊपर उठकर करना होगा। उन्होंने कहा कि यह समस्या किसी एक राज्य या सरकार तक सीमित नहीं रही है, बल्कि कई राज्यों में अलग-अलग समय पर ऐसे मामले सामने आए हैं।

छात्रों को आगे करके राजनीति कर रहा है विपक्ष : धामी

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि विपक्ष को छात्रों के हित से कोई मतलब नहीं है बल्कि उन्हें तो बस छात्रों को आगे करके राजनीति करना है। सीएम धामी का यह बयान उस वक्त आया है जब पीएम मोदी ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि पेपर लीक करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और पेपर लीक मामलों की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होंगे। देहरादून में सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष का रवैया बहुत नकारात्मक है। वे पहले ही अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं और अब छात्रों को आगे करके राजनीति करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के एक्स पर किए गए पोस्ट का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि पेपर लीक जैसे मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।



राहुल गांधी नीट पर चर्चा से भाग रहे : सरावगी

पटना। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने गुरुवार को कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संसद में नीट और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष जानबूझकर बहस से बच रहा है और छात्रों के आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है। पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में संजय सरावगी ने कहा कि यह समय छात्रों की समस्याओं का समाधान निकालने का है, न कि उन पर राजनीति करने का। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में किसी भी नियम के तहत और जितनी देर तक चर्चा करनी हो, उसके लिए तैयार है। यदि विपक्ष के पास कोई ठोस सुझाव है तो उसे सदन में रखना चाहिए, लेकिन संसद की कार्यवाही बाधित कर देश का समय और संसाधन बर्बाद करना उचित नहीं है।

छात्रों के भविष्य पर राजनीति नहीं हो : नीरज कुमार

पटना। जनता दल (यूनाइटेड) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने नीट पेपर लीक, छात्रों के विरोध-प्रदर्शन, वक्फ संपत्तियों से जुड़े उम्मीद पोर्टल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनसीपी प्रमुख शरद पवार व सांसद सुप्रिया सुले की मुलाकात समेत कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गंभीर विमर्श होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। नीट पेपर लीक मामले पर नीरज कुमार ने कहा कि सरकार यह स्वीकार कर चुकी है कि इस मामले में गलती हुई है। देश के छात्र, उनके अभिभावक और आम जनता की अपेक्षा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की बात का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पर भरोसा किया जाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर संसद में व्यापक बहस होनी चाहिए और विपक्ष को चर्चा से बचने के बजाय अपने सुझाव रखने चाहिए। केवल आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार, कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और पूर्व में विभिन्न राज्यों में हुए प्रश्नपत्र लीक मामलों की भी समीक्षा होनी चाहिए। कांग्रेस सरकारों के दौरान हुए कथित प्रश्नपत्र लीक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई थी। यह राजनीतिक नहीं बल्कि छात्र हित का विषय है और सरकार अपना एक्शन प्लान प्रस्तुत करेगी, इसलिए छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति का एजेंडा तय नहीं किया जाना चाहिए।

विपक्ष चर्चा के लिए आगे आए : पाल

वहीं, भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा दोनों ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार इस विषय पर जितनी देर तक विपक्ष चाहे, उतनी देर तक चर्चा के लिए तैयार है। इसके बावजूद विपक्ष लगातार हंगामा कर संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।

सरकार चर्चा को तैयार

भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने भी कहा कि सरकार हर स्तर पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केवल संवाद और बहस के माध्यम से ही किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने विपक्ष से कहा कि वह संसद की कार्यवाही में भाग लेकर छात्रों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा करे।

छात्रों का आंदोलन राजनीतिक तौर से हाईजैक हो चुका है : रिजु दत्ता

कोलकाता। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर टीएमसी के निलंबित नेता रिजु दत्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है। रिजु दत्ता ने कहा, नीट पेपर लीक की वजह से बच्चों ने आत्महत्या की। पेपर लीक बंद होना चाहिए और बच्चों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन छात्रों के आंदोलन में असामाजित तत्व भी घुस गए हैं। छात्र आंदोलन में तलवार ले जाने की क्या जरूरत है ये कौन लोग हैं जो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं पूरा आंदोलन राजनीतिक तौर से हाईजैक हो चुका है।



छात्रों को पीएम मोदी की बातों पर भरोसा रखना चाहिए : निषाद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने पेपर लीक के मामलों और छात्रों के विरोध-प्रदर्शन सहित कई और मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। संजय निषाद ने कहा, देश के लोगों को पीएम मोदी की बातों का समर्थन करना चाहिए और छात्रों को भरोसा रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जिस चीज को ठानते हैं, उसको पूरा करते हैं। जब उन्होंने कह दिया है तो सब सजा के पात्र होंगे, कड़े नियम बनाए जाएंगे और तेजी से भ्रष्टाचार को रोका जाएगा। पीएम मोदी के इस बात का हम सभी को स्वागत करना चाहिए। छात्रों को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए और उनको प्रधानमंत्री पर भरोसा रखना चाहिए। अन्ना हजारे की ओर से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने को लेकर संजय निषाद ने कहा कि छात्रों के साथ सरकार खड़ी है। जब छात्र विरोधियों के साथ गुमराह होंगे तो शासन-प्रशासन व्यवस्था बनाता है। मेरा मानना है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।



संक्षिप्त समाचार

पवार की पीएम से मुलाकात और सलमान खान के बयान पर बोले आनंद दुबे- पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा

मुंबई, एजेंसी। शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। इसके साथ ही आनंद दुबे ने पीएम मोदी के नीट पेपर लीक मामले को लेकर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध-प्रदर्शन पर अभिनेता सलमान खान के बयान पर भी टिप्पणी की। शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि शरद पवार ने बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि उन्होंने पीएम मोदी से कुछ विशेष मुद्दों को लेकर मुलाकात की है। इन मुद्दों में छात्रों के प्रदर्शन, महाराष्ट्र किसानों से संबंधित विषय जैसे कई मामले थे। शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी आपस में गुरु-शिष्य का रिश्ता भी बताते हैं। हालांकि, राजनीति किस करवट जाएगी, यह किसी को नहीं पता है। उन्होंने कहा कि पहले दिन ही छात्रों से बात हो जानी चाहिए थी। हर विवाद का समाधान संवाद होता है। आइए, संवाद कीजिए और विषय को समाप्त कीजिए।



सांसद पवन खेड़ा असम पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने हुए पेश

गुवाहाटी, एजेंसी। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा गुरुवार को असम पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। यह पेशी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दायर मानहानि के एक मामले के सिलसिले में हुई। खेड़ा नई दिल्ली से गुवाहाटी पहुंचे और जांच एजेंसी के बुलावे पर क्राइम ब्रांच मुख्यालय गए। इससे पहले उन्होंने सेहत की समस्याओं और पहले से तय राजनीतिक कामों का हवाला देते हुए तय तारीखों पर पेश होने से छूट मांगी थी। क्राइम ब्रांच ऑफिस में जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए खेड़ा ने कहा कि वह समन का पालन कर रहे हैं और जांच में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे जारी किए गए नोटिस के जवाब में क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ हूं। इससे पहले मैंने जांच एजेंसी को बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और पार्टी के पहले से तय कार्यक्रम भी हैं। उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया। क्राइम ब्रांच ने हाल ही में खेड़ा को 17 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया था, क्योंकि वह पहले तय तारीखों पर पेश नहीं हो पाए थे।

नीट विफल हो चुकी है, इसे खत्म करने का समय आ गया : स्टालिन



चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रमुक (डीएमके) अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को लेकर केंद्र सरकार पर हमला तेज करते हुए कहा कि यह परीक्षा अपने घोषित उद्देश्यों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से नीट को समाप्त करने की मांग दोहराई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए स्टालिन ने कहा कि जिस उद्देश्य से नीट लागू की गई थी, वह किसी भी मोर्चे पर सफल नहीं हुई। उनके मुताबिक, इससे न तो छात्रों का शैक्षणिक दबाव कम हुआ, न शिक्षा के व्यावसायीकरण पर रोक लगी और न ही शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार आया। उन्होंने कहा कि नीट ने पढ़ाई का केंद्र स्कूलों से हटाकर निजी कोचिंग संस्थानों की ओर कर दिया है, जिससे मेडिकल प्रवेश की तैयारी कर रहे छात्रों और उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक और मानसिक बोझ बढ़ा है। स्टालिन ने कहा कि नीट की समस्याएं केवल प्रक्रिया से जुड़ी नहीं हैं, बल्कि इसकी पूरी व्यवस्था में ही खामियां हैं। उन्होंने कहा कि हाल के घटनाक्रमों ने तमिलनाडु द्वारा वर्षों से उठाई जा रही चिंताओं को सही साबित किया है। उन्होंने कहा, छात्रों का जारी विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के लिए चेतावनी है। अब समय आ गया है कि केंद्र राज्यों पर भरोसा करे और नीट को समाप्त करे। स्टालिन की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब उन्होंने एक दिन पहले नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया था। छात्र परीक्षा में कथित अनियमितताओं के बाद सुधार और नीट को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन करते हुए स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु ने शुरुआत से ही चेतावनी दी थी कि नीट बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और मेडिकल शिक्षा में असमान अवसरों को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि डीएमके ने शुरू से ही नीट का विरोध किया है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय की अवधारणा को कमजोर करता है और ग्रामीण क्षेत्रों, सरकारी स्कूलों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के साथ अन्याय करता है। तमिलनाडु के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराते हुए स्टालिन ने कहा कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने वाला राज्य आज भी नीट को पूरी तरह खत्म करने की मांग पर कायम है। उन्होंने केंद्र सरकार से देशभर के छात्रों की बढ़ती चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल प्रवेश के लिए अधिक न्यायसंगत और समान अवसर सुनिश्चित करने वाली नई व्यवस्था लागू करने की अपील की।

श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति की बैठक संपन्न

रामानंदी परंपरा के अनुसार होंगे धार्मिक अनुष्ठान : रामानंद दास

अयोध्या, एजेंसी

श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति ने गुरुवार को मंदिर की पूजा पद्धति को लेकर बैठक की। राम मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति के सदस्य रामानंद दास जी महाराज ने कहा कि सभी धार्मिक अनुष्ठान रामानंदी परंपरा के अनुसार किए जाएंगे। रामानंद दास जी महाराज ने समाचार एजेंसी कहा कि मंदिर की पूजा पद्धति यथावत चल रही है। अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होगी तो सभी लोग मिलकर फैसला करेंगे। हालांकि, पूजा पद्धति में हमें किसी प्रकार का दोष नहीं मालूम पड़ रहा है।

धार्मिक समिति में पांच नए संतों को शामिल करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी अयोध्या के विशिष्ट महापुरुष हैं। ये सभी संत पहले से ही श्रीराम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ऐसे महापुरुषों का सहयोग लिया जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। राम मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति के सदस्य कमल नयन दास ने कहा, समिति की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है। यह मंदिर के त्योहारों, रीति-रिवाजों, चढ़ावे और पुजारियों के प्रबंधन की देखरेख करती है। इसके अलावा समिति की कोई और भूमिका नहीं है। राम वल्लभ कुंज के उत्तराधिकारी और राम मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने कहा, रामानंदी वैष्णव वैदिक परंपरा के अनुसार, ठाकुरजी की पूजा से जुड़ी सभी रीतियों और प्रथाओं का पालन किया जाएगा—जिसमें सेवा, पूजा, आरती, शयन, भोग, त्योहार और समय शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे वरिष्ठ संत और समिति के सम्मानित सदस्य इस बात पर विचार-विमर्श करेंगे कि श्रीराम जन्मभूमि से जुड़ी परंपराओं को ठाकुर जी की सेवा और पूजा में पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ कैसे निभाया जा सकता है।



अहम बैठक में होगी चढ़ावे पर चर्चा

श्रीराम आश्रम के महंत जयराम दास कहते हैं, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज के आश्रम, मणिराम दास छावनी में एक अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में शामिल होने के लिए अयोध्या भर के संतों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में मंदिर में चढ़ावे (दान) से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होगी। राम कचहरी चार धाम मंदिर के महंत शशिकांत दास ने कहा, राम मंदिर को लेकर कई तरह की चर्चाएं, अफवाहें और आरोप फैल रहे हैं और देश भर के लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने इन अफवाहों और चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक सेमिनार आयोजित किया है।

कांग्रेस पर बरसे शाहनवाज हुसैन

'शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं चलाते'

पटना, एजेंसी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर तीखा हमला किया।

उन्होंने कहा कि शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं चलाते हैं। पटना में बातचीत में शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 'शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं चलाते। कांग्रेस ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हैं। माओवादियों और नक्सलियों जैसी हरकतें अब कांग्रेस कर रही है।'

उन्होंने आरोप लगाया, 'भाजपा कार्यालय के बाहर पहले भी विरोध-प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन हमने कभी पेशेवर गुंडे नहीं बुलाए और न ही पत्थर जमा किए। कांग्रेस ने कथित तौर पर ट्रकों में भरकर पत्थर मंगवाए थे और सोची-समझी साजिश के तहत लाठी-डंडे लेकर लोगों को बुलाया था।' हुसैन ने चेतावनी देते हुए कहा, 'कांग्रेस नेताओं को पता होना चाहिए कि उन्होंने जो हरकतें की हैं, उनका कड़ा जवाब दिया जाएगा। पुलिस को सारी फुटेज दे दी गई हैं और कार्रवाई होगी।'

मोदी के बयान का स्वागत

हुसैन ने पेपर लीक मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के बयान का स्वागत किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा, प्रधानमंत्री ने देश के छात्रों और युवाओं को एक सीधा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि पेपर लीक की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इसमें शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी दल आंदोलन के कंधे पर सवार होना चाहते हैं। मुद्दाविहीन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों के भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है।



पीएम को युवाओं की चिंता

शाहनवाज हुसैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा देश के युवाओं की फिक्र की है और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए दिन-रात जुटे रहते हैं। पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने का ऐलान ऐतिहासिक है। यह जाहिर करता है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी सरकार का संकल्प अडिग है। विपक्ष छात्रों की आड़ में राजनीतिक रोटी सेंकने की कोशिश बंद करे। ये वक्त उन्हें भड़काने का नहीं बल्कि दलीय राजनीति से ऊपर उठकर छात्रों के हित में मिलकर फैसले लेने का है।

बांकीपुर उपचुनाव : भाजपा ने तेज किया प्रचार

'अपनी सरकार, अपना विधायक' के लगे नारे

पटना, एजेंसी

बिहार की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है।

भाजपा, जन सुराज और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) इस सीट पर अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा ने इस सीट से नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार किसी चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं। दूसरी ओर, राजद ने रेखा गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनावी सरगर्मियों के बीच राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुकाबला त्रिकोणीय है, हालांकि भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। चुनाव प्रचार को धार देने के लिए भाजपा ने नया चुनावी पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में 'अपनी सरकार, अपना विधायक' का नारा प्रमुखता से दिया गया है। इसके साथ ही नीरज कुमार सिन्हा को 'बांकीपुर का बेटा' बताते हुए मतदाताओं से कमल के निशान पर वोट देने की अपील की गई है। पोस्टर में यह संदेश भी दिया गया है कि 'अपना वोट क्यों खराब करना' और स्थानीय उम्मीदवार ही क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझकर उनका समाधान कर सकता है।



स्थानीय मुद्दे बन रहे एजेंडा

भाजपा ने अपने प्रचार अभियान में 'स्थानीय मुद्दे, स्थानीय समाधान' और विकास को प्रमुख चुनावी एजेंडा बनाया है। पार्टी का कहना है कि राज्य और केंद्र में एक ही गठबंधन की सरकार होने से क्षेत्र के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। प्रचार अभियान के दौरान स्थानीय नेतृत्व भी लगातार मतदाताओं के बीच पहुंचकर भाजपा के पक्ष में समर्थन जुटाने में लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बांकीपुर का प्रतिनिधित्व पहले भी स्थानीय चेहरों ने किया है और आगे भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व स्थानीय उम्मीदवार को ही करना चाहिए। उनका मानना है कि क्षेत्र की समस्याओं और जरूरतों को वही बेहतर तरीके से समझ सकता है, जो लंबे समय से बांकीपुर से जुड़ा रहा हो। भाजपा की प्रदेश महामंत्री प्रीति शेखर ने कहा कि उनकी पार्टी विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्याशी बांकीपुर का निवासी है और जनता का व्यापक समर्थन पार्टी को मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी।

उप्र के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा

आस्थावान बनने का ठेका ले रहे आस्था पर प्रहार करने वाले : योगी

गोरखपुर, एजेंसी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था, सुरक्षा व विकास के मुद्दे पर कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा सत्ता में रहने के दौरान आस्था पर प्रहार करने वाले सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले रहे हैं।

कांग्रेस व सपा के लोगों के मुंह से आस्था के उपदेश हास्यास्पद लगते हैं। सपा ने अपने शासन में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में बाधा डाली, रामभक्तों पर गोली चलवाई। कांग्रेस ने भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, मंदिर आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा किया। ये लोग किस मुंह से आस्था की बात कर रहे हैं?



सीएम योगी गुरुवार को गोरखपुर जिले के पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के उपरांत कहा कि कांग्रेस-सपा ने अपनी सरकारों में न केवल आस्था से खिलवाड़ किया, बल्कि युवाओं को नौकरी और रोजगार से वंचित किया, अन्नदाता किसानों का हक छीना। बहन-बेटियों व व्यापारियों की सुरक्षा पर संकट खड़ा किया। 2017 के पहले यूपी में आए दिन दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी। होली, दुर्गापूजा, विजयदशमी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पर्वों पर दंगे होते थे, कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। अब इन्हीं दलों के लोग आस्था पर बड़े-बड़े हास्यास्पद उपदेश दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने 2017 के पहले इंसेफेलाइटिस को लेकर सरकारी उदासीनता, सुरक्षा और निवेश के बदतर हालात को लेकर भी कांग्रेस-सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंसेफेलाइटिस बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश की नियति बन चुकी थी। हजारों बच्चों की मौत हो गई, पर पिछली सरकारें कान में रुई डालकर सोती रहीं।

अच्छी सरकार आती है तो अच्छा कार्य होता है

उन्होंने कहा कि जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छा कार्य होता है। जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उसके सकारात्मक और प्रगतिशील परिणाम आते हैं। डबल इंजन सरकार आने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश से इंसेफेलाइटिस को समाप्त कर दिया गया। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने हैं। गोरखपुर में एम्स बना और बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी चिकित्सा का बेहतरीन केंद्र बन चुका है। गोरखपुर में 1990 से बंद खाद कारखाना चालू हो चुका है। इससे किसानों को समय से खाद उपलब्ध हो रही है। किसानों को बीज और खाद समय पर उपलब्ध हो तो उत्पादन अच्छा होता है। जब किसान खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। गोरखपुर में मुक्तेश्वरनाथ मंदिर का पुनरोद्धार हो गया है, झारखंडी महादेव मंदिर के पुनरोद्धार के लिए भी प्रस्ताव मांगा गया है। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर का रामगढ़ताल पर्यटन का सबसे बड़ा और बेहतरीन केंद्र बन गया है। जबकि 10 वर्ष पूर्व इसकी पहचान सुनसान स्थल, गंदगी और मच्छर के कारण थी।

संक्षिप्त समाचार

छात्र आंदोलन पर सोनिया गांधी बोलीं– उनके साथ खड़ा होना हमारा राजनीतिक और संवैधानिक कर्तव्य

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को परीक्षा के पेपर लीक होने को लेकर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन से निपटने के केंद्र सरकार के तरीके की आलोचना की और आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था गहरे संकट का सामना कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर एक लेख शेयर किया, जिसमें पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, फ्रमोदी सरकार बातचीत के बजाय अक्सर हिंसा का सहारा लेती है। किसानों से लेकर एक्टिविस्ट तक, यह पैटर्न साफ दिखता है। केंद्र सरकार ने न सिर्फ भारत के शिक्षा जगत को नुकसान पहुंचाया है बल्कि बिना किसी डर के काम करने, खुद को ही सही मानने और पूरी तरह असंवेदनशील होने की आदत भी बना ली है। भारत के छात्रों ने मोदी सरकार के दावों की असलियत उजागर कर दी है। सोनिया गांधी ने शिक्षा व्यवस्था का पतन, युवा भारत का सदमा शीर्षक वाले अपने लेख में लिखा कि परीक्षा के पेपर लीक होने और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में जोर पकड़ चुका है और उनकी मांगें जवाबदेही और सुधारों पर केंद्रित हैं। दिल्ली में 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए गांधी ने लिखा, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने बेरहमी से लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करके और बिना वजह हिंसा के जरिए उन्हें दबाने की कोशिश की। ये हमारे बेटे-बेटियां और युवा हैं। कांग्रेस नेता ने सरकारी शिक्षा, परीक्षा में सुधार और जवाबदेही के तरीकों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी शिक्षा में घटते निवेश, निजी संस्थानों पर बढ़ती निर्भरता और परीक्षा प्रणाली की समस्याओं ने छात्रों और परिवारों पर अतिरिक्त दबाव डाला है। परीक्षा में गड़बड़ियों पर सोनिया गांधी ने लिखा कि टेस्टिंग सिस्टम केंद्रीकरण, निजीकरण और राजनीतिकरण से प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार पेपर लीक होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों का भरोसा कम हुआ है।


Sonia Gandhi

अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशन बंद, डीएमआरसी ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। सीजेपी के प्रदर्शन का असर दिल्ली-एनसीआर की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो पर दिखाई दे रहा है। इसी बीच, मेट्रो के कई स्टेशन को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने गुरुवार को यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण ट्रेवल एडवाइजरी जारी करते हुए बताया, 24 जुलाई (शुक्रवार) सुबह 7.30 बजे से अगले आदेश तक राजधानी के कई प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि, कुछ प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर यात्रियों को लाइन बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। डीएमआरसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट में कहा, फ्सुरक्षा और परिचालन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। यात्रियों से यात्रा की योजना पहले से बनाने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है। डीएमआरसी के अनुसार, जिन मेट्रो स्टेशनों को सुबह 7.30 बजे से अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा, उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान शामिल हैं। डीएमआरसी ने पोस्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर यात्रियों के लिए इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इन स्टेशनों पर यात्री मेट्रो लाइन बदल सकेंगे, लेकिन स्टेशन से बाहर निकलने या अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले बुधवार को भी सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद रखा गया था। हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा दी गई थी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया था कि अगले आदेश तक लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरियट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे।



कश्मीर घूमने जा रहे यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन का संचालन

नई दिल्ली। भारी बारिश और खराब मौसम के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात धीमा होने से कश्मीर घाटी में फंसे यात्रियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर रेलवे जम्मू मंडल' द्वारा गुरूवार को श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक एक विशेष ट्रेन का संचालन किया गया। यह निर्णय वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल के निर्देश पर यात्रियों की सुविधा एवं आरामदायक आवागमन सुनिश्चित करने के लिए तुरंत प्रभाव से लिया गया है। इस विशेष ट्रेन ने 23 जुलाई 2026 को शाम 17.10 बजे श्रीनगर रेलवे स्टेशन से प्रस्थान किया। मार्ग में यह ट्रेन बनिहाल रेलवे स्टेशन पर ठहराव करते हुए 'रात्रि 20.15 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा' पहुंचेगी। विशेष ट्रेन की सुविधा का लाभ लगभग 600 से अधिक यात्रियों ने उठाया। इस विशेष ट्रेन के संचालन से कश्मीर घाटी में फंसे यात्रियों को सुरक्षित एवं त्वरित यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहायता मिलेगीए विशेषकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा और जम्मूतवी से आगे की ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को। इससे पूर्व भी जम्मू मंडल द्वारा यात्रियों को बेहतर एवं आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए समय.समय पर विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाता रहा है। इस संबंध में 'वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जम्मू श्री उचित सिंघल ने कहा कि यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सड़क यातायात धीमा होने तथा यात्रियों को समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मंडल प्रशासन द्वारा त्वरित निर्णय लेकर यह विशेष ट्रेन चलाई जा रही है ताकि किसी भी यात्री को असुविधा न हो।



'मेड इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन' को स्वच्छ ऊर्जा का प्रतीक बनाने के लिए काम करें : श्रीपाद नाइक

नई दिल्ली। केंद्रीय विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने फिक्की द्वारा आयोजित द्वितीय भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा, 'आज सवाल यह नहीं है कि ग्रीन हाइड्रोजन औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन का प्रमुख आधार बनेगा या नहीं, बल्कि यह है कि इस परिवर्तन का नेतृत्व कौन-सा देश करेगा। भारत के पास वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की अद्वितीय क्षमता है। आइए, हम सब मिलकर 'मेड इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन' को स्वच्छ ऊर्जा, तकनीकी उत्कृष्टता और सतत औद्योगिक विकास का दुनिया का सबसे भरोसेमंद प्रतीक बनाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ने देश में एक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। उत्पादन प्रोत्साहन, स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण, रिफाइनरी एवं उर्वरक क्षेत्रों में मांग सृजन, मोबिलिटी, शिपिंग और इस्पात क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएं तथा अनुकूल नियामकीय ढांचा नीतिगत सोच को व्यावसायिक वास्तविकता में बदल रहे हैं। नाइक ने कहा कि 'भारत में ग्रीन हाइड्रोजन अब भविष्य की अवधारणा नहीं, बल्कि तेजी से उभरता हुआ आर्थिक अवसर बन चुका है। व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन से लेकर हाल ही में देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन के शुभारंभ तक, हमारी उपलब्धियां भारत को वैश्विक हाइड्रोजन हब बनाने की दिशा में हमारी व्यापक क्षमताओं को दर्शाती हैं।



सीएक्यूएम का 'ऑपरेशन क्लीन एयर'

एनसीआर में 64 सड़कों का निरीक्षण, मिला मानकों का उल्लंघन

नई दिल्ली, एजेंसी

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने और सड़कों से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने फरीदाबाद और गुरुग्राम में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। यह अभियान ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत 22 जुलाई को चलाया गया।

सीएक्यूएम ने बताया कि इस निरीक्षण का उद्देश्य आयोग द्वारा जारी शहरी सड़कों की री-डेवलपमेंट और पक्कीकरण के मानक फ्रेमवर्क के अनुसार किए जा रहे कार्यों की स्थिति की जांच करना था।

निरीक्षण के लिए आयोग की ओर से तैनात 9 फ्लाइंग स्क्वॉड ने फरीदाबाद नगर निगम और गुरुग्राम नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों की जांच की।

अभियान के दौरान कुल 64 सड़क हिस्सों का निरीक्षण किया गया, जिनकी कुल लंबाई करीब 31 किलोमीटर थी। इनमें फरीदाबाद की 50 सड़कें और गुरुग्राम की 14 सड़कें शामिल थीं। निरीक्षण में 10 मीटर से कम और 10-15 मीटर चौड़ी सड़कों को भी शामिल किया गया।

सीएक्यूएम के अनुसार, निरीक्षण में 49 सड़क हिस्सों पर पूरी तरह से एंड-टू-एंड पक्कीकरण पाया गया। इनमें फरीदाबाद की 38 सड़कें और गुरुग्राम की 11 सड़कें शामिल हैं।

वहीं, 15 सड़क हिस्सों पर अभी तक पूरा पक्कीकरण नहीं हुआ था। इनमें फरीदाबाद की 12 सड़कें और गुरुग्राम की 3 सड़कें शामिल हैं। आयोग ने कहा कि इन जगहों पर अभी काम पूरा किया जाना बाकी है। सीएक्यूएम ने बताया कि फरीदाबाद और गुरुग्राम नगर निगमों ने दावा किया था कि सड़कों का विकास मानक फ्रेमवर्क के अनुसार किया गया है, लेकिन निरीक्षण के दौरान कुछ जगहों पर नियमों का पालन नहीं पाया गया। आयोग ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करें और उनके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।

सीएक्यूएम ने कहा कि शहरी सड़कों का सही तरीके से एंड-टू-एंड पक्कीकरण सड़क की धूल को दोबारा हवा में फैलने से रोकने के लिए बेहद जरूरी है। इससे वाहनों की आवाजाही से उड़ने वाली धूल कम होगी और मैकेनिकल रोड स्वीपिंग जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपाय अधिक प्रभावी होंगे।

आयोग ने सभी सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे बाकी बचे विकास कार्यों को जल्द पूरा करें और तय मानकों के अनुसार सड़कों का निर्माण सुनिश्चित करें। सीएक्यूएम ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में सड़क धूल से होने वाले प्रदूषण को लंबे समय तक नियंत्रित करने के लिए सभी एजेंसियों द्वारा मानक फ्रेमवर्क लागू करना जरूरी है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 'ऑपरेशन क्लीन एयर' के तहत पूरे एनसीआर में निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की निगरानी की जा सके और जरूरत पड़ने पर समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।



सड़क का एंड-टू-एंड पक्कीकरण जरूरी

सीएक्यूएम ने कहा कि शहरी सड़कों का सही तरीके से एंड-टू-एंड पक्कीकरण सड़क की धूल को दोबारा हवा में फैलने से रोकने के लिए बेहद जरूरी है। इससे वाहनों की आवाजाही से उड़ने वाली धूल कम होगी और मैकेनिकल रोड स्वीपिंग जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपाय अधिक प्रभावी होंगे। आयोग ने सभी सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे बाकी बचे विकास कार्यों को जल्द पूरा करें और तय मानकों के अनुसार सड़कों का निर्माण सुनिश्चित करें।

सिविल लाइंस में जलभराव का होगा स्थायी समाधान

नई दिल्ली, एजेंसी

उत्तर दिल्ली के सिविल लाइंस क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। दिल्ली सरकार ने मेटकॉफ हाउस रेगुलेटर पर आधुनिक स्थायी पंप हाउस का लोकार्पण किया। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग एवं जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इस स्थायी पंप हाउस का लोकार्पण किया।

यह सुविधा दिल्ली में बाढ़ और जलभराव प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अवसर पर प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि वर्षों से यमुना का जलस्तर बढ़ने और मेटकॉफ हाउस रेगुलेटर को बंद किए जाने के दौरान सिविल लाइंस क्षेत्र के निवासियों और राहगीरों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता था। रेगुलेटर बंद होने के कारण आसपास के क्षेत्रों का बरसाती पानी सामान्य रूप से बाहर नहीं निकल पाता था और आवासीय क्षेत्रों, सड़कों तथा गलियों में पानी जमा हो जाता था। मंत्री ने कहा कि दिल्ली की एक और बड़ी यातायात और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान किया गया है। जब भी यमुना का जलस्तर बढ़ता था और मेटकॉफ हाउस रेगुलेटर को बंद करना पड़ता था, तब सिविल लाइंस क्षेत्र का बरसाती पानी वापस आकर सड़कों, गलियों और कई बार घरों तक में जमा हो जाता था।

हर वर्ष अस्थायी पंप लगाने पड़ते थे। अब इस अस्थायी व्यवस्था को स्थायी समाधान से बदल दिया गया है। नवनिर्मित स्थायी पंप हाउस के माध्यम से यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण रेगुलेटर बंद रहने की स्थिति में बरसाती पानी की तेज और प्रभावी निकासी सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे बाढ़ और भारी बारिश के दौरान क्षेत्र की तैयारियों को मजबूती मिलेगी तथा आपातकालीन व्यवस्थाओं और अस्थायी पंपिंग सिस्टम पर निर्भरता कम होगी।

आधुनिक पंप हाउस में 75 हॉर्स पावर के तीन सबमर्सिबल पंप और 35 हॉर्स पावर का एक सबमर्सिबल पंप लगाया गया है। इनकी संयुक्त पंपिंग क्षमता लगभग 2,500 किलोलीटर प्रति घंटे है। बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में पंपिंग व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए 250 केवीए का डीजी सेट भी स्थापित किया गया है।



अगली सुनवाई 3 अगस्त को

नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा सुधारों का रोडमैप

नई दिल्ली, एजेंसी

नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए व्यापक सुधार किए जा रहे हैं।

केंद्र सरकार ने कहा कि पूरी सुधार प्रक्रिया पर सर्वोच्च स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि सरकार के लिए बच्चों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर गंभीरता से काम किया जा रहा है और जल्द ही सरकार इस संबंध में विस्तृत जानकारी अदालत के सामने रखेगी। तुषार मेहता ने कहा कि सरकार प्रश्नपत्र की छपाई से लेकर परीक्षा केंद्रों तक उसके सुरक्षित पहुंचने और छात्रों तक पूरी प्रक्रिया का विस्तृत ब्योरा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि राधाकृष्णन समिति की सभी सिफारिशों को लागू किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार अपने हलफनामे में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी भी देगी।



डीयू व संबद्ध कॉलेजों में महिला सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी लगाने की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में 28 जुलाई से शुरू होने वाले शैक्षिक सत्र 2026-27 से पहले महिला छात्राओं और शिक्षिकाओं की सुरक्षा को लेकर फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस (शिक्षक संगठन) ने विश्वविद्यालय प्रशासन से सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की।

संगठन ने कुलपति प्रो. योगेश सिंह को पत्र लिखकर नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस तथा डीयू से संबद्ध कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने, महिला पुलिस की तैनाती और ओरिएंटेशन कार्यक्रमों के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की। फोरम के अध्यक्ष प्रो. हंसराज सुमन ने कहा कि देशभर में चल रहे विभिन्न आंदोलनों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई को नए छात्रों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान कॉलेजों के बाहर महिला पुलिस और महिला सुरक्षा गार्डों की तैनाती की जानी चाहिए तथा पूरे परिसर की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होनी चाहिए। प्रो. सुमन ने बताया कि विश्वविद्यालय ने पहले भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्सवों के दौरान महिला शौचालयों एवं ग्रीन रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए थे। इसी तरह नियमित दिनों में भी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।



मूवमेंट डिसऑर्डर के इलाज पर व्यापक चर्चा

नई दिल्ली। फोकस्ड अल्ट्रासाउंड के जरिए जिंदगी को फिर से बेहतर बनाना' थीम पर आधारित वट्टीकुटी फाउंडेशन ने न्यूरोनेक्स्ट फोरम की नई श्रृंखला का सफल आयोजन किया। यह देशव्यापी मरीज जागरुकता अभियान अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली और चंडीगढ़ में आयोजित हुआ, जिसमें 400 से ज्यादा मरीजों, उनके परिजनों और देखभाल करने वाले लोगों ने हिस्सा लिया। प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट्स और न्यूरोसर्जन्स ने सीधे संवाद के जरिए प्रतिभागियों ने पार्किंसन डिजीज, एसेंशियल ट्रेमर और इलाज के नए विकल्पों को बेहतर तरीके से समझा, ताकि वे अपने इलाज को लेकर ज्यादा जागरूक और सही निर्णय ले सकें। फोरम में देश के कई प्रमुख न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ शामिल हुए। अहमदाबाद स्थित एसएमटी.एनएचएल म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. सुधीर वी. शाह, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के कंसल्टेंट फंक्शनल न्यूरोसर्जन डॉ. अनिरुद्ध भगवत, नई दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी विभाग की सीनियर कंसल्टेंट को-चेयरपर्सन डॉ. अंशु रोहतगी तथा वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजिकल साइंसेज विभाग के प्रोफेसर सहित कई विशेषज्ञ मौजूद रहे।

हमारा आंदोलन सफल रहा, सरकार ने प्रमुख मांगें मानीं : गीतांजलि आंग्मो

गुरुग्राम, एजेंसी

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लिखित आश्वासन मिलने के बाद यह कदम उठाया है।

डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने शुक्रवार को कहा, सोनम वांगचुक ने लिखित आश्वासन के साथ छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। छात्र नेता सरकार के साथ बैठक के बाद ही विरोध प्रदर्शन की आगे की रणनीति तय करेंगे।

सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने कहा, गुरुवार आधी रात को हमें सरकार से लिखित में आश्वासन मिला कि वे हमारी मांगें मान रहे हैं, जिसमें विरोध प्रदर्शन करने वाले चात्रों के खिलाफ कोई एफआईआर न करना, नीट पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या करने वाले बच्चे के परिजनों को मुआवजा देना और संसद में एजुकेशन एग्जाम और रिफॉर्म्स पर चर्चा करना शामिल है।

डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने कहा, सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुवार को सरकार की तरफ से यहां आए थे। उससे पहले, 16 सांसद यहां आए और विपक्ष के 65 सांसदों ने लिखित आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होगी। सरकार और विपक्ष ने तय किया है कि एजुकेशन रिफॉर्म्स पर चर्चा इसी मानसून सत्र में होगी। यह हमारे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है क्योंकि सत्ता और विपक्ष ने निर्णय लिया है कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर चर्चा मानसून सत्र में होगी।

आंग्मो ने कहा ने कहा, हमारे आंदोलन ने पूरे देश को जगा दिया है। नीट पेपर लीक एक लक्षण था लेकिन असली वजहें सिस्टम में मौजूद हैं। हमें उम्मीद है कि यह सरकार के लिए एक चेतावनी भरी सीख होगा। यह एक सफल आंदोलन रहा है और इसीलिए सोनम वांगचुक ने अपना उपवास खत्म कर दिया। शनिवार से वह सेमी-सॉलिड डाइट लेना शुरू करेंगे।



छात्र आंदोलन में भी पहला संपर्क सिविल डिफेंस का होना चाहिए : किरण बेदी

'सिविल डिफेंस बने पहली सुरक्षा पंक्ति', छात्र आंदोलनों पर किरण बेदी का सुझाव

नई दिल्ली, एजेंसी

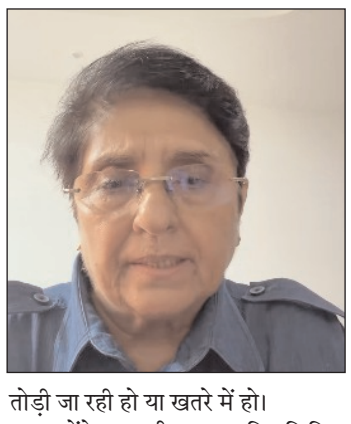
पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने सुझाव दिया कि छात्र विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए दंगा-रोधी पुलिस के बजाय सिविल डिफेंस के जवानों को सुरक्षा की पहली पंक्ति के तौर पर तैनात किया जा सकता है। इससे पुलिस बल के साथ सीधे टकराव और उन पर लगने वाले आरोपों से बचा जा सकेगा।

यह सुझाव ऐसे समय में आया है, जब 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में हुए संसद चलो मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता के लिए दिल्ली पुलिस की आलोचना हो रही थी।

उन्होंने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट वीडियो में कहा, ठीक उसी तरह जैसे सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) तैनात होती है और सैनिक सीधे संपर्क में नहीं आते। बॉर्डर पर पहला संपर्क बीएसएफ का होता है। वैसे ही छात्र आंदोलन में भी पहला संपर्क सिविल डिफेंस का होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि सिविल डिफेंस के पास केन शील्ड, बॉडी आर्मर और हेलमेट हो सकते हैं, लेकिन इस बल के पास लाठियां नहीं होंगी। दंगा-रोधी पुलिस दूर रहकर स्थिति पर नजर रख सकती है और आम तौर पर जानमाल की, खास तौर पर सिविल डिफेंस की सुरक्षा कर सकती है।

किरण बेदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि दंगा-रोधी पुलिस को तभी आना चाहिए जब सिविल डिफेंस की लाइन तोड़ी जा रही हो या खतरे में हो।



उन्होंने यह भी बताया कि सिविल डिफेंस हर राज्य में मौजूद है। बेदी ने कहा, इसका मतलब है कि हम छात्र आंदोलनों के लिए उन्हें तेजी से इकट्ठा कर सकते हैं, दोबारा ट्रेनिंग दे सकते हैं और तैनात कर सकते हैं। इस तरह पुलिस बल के साथ टकराव और आरोपों से बचा जा सकता है। काफी समय और ऊर्जा की बचत हो सकती है। पूर्व पुलिस अधिकारी ने वीडियो के आखिर में कहा,यह एक ऐसा विचार है, जिस पर गौर किया जाना चाहिए।

किरण बेदी ने बताया कि हर राज्य में सिविल डिफेंस और होम गार्ड के सदस्य भर्ती किए गए युवा पुरुष और महिलाएं होते हैं जो पे-रोल पर होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सिविल डिफेंस छात्र प्रदर्शनकारियों के संपर्क का पहला जरिया बनता है, तो इससे छात्र प्रदर्शनकारियों पर यह जिम्मेदारी होगी कि वे दंगा-रोधी पुलिस को बुलाने के लिए उकसाने वाली हरकत न करें।

महत्वपूर्ण विचार

किरण बेदी ने बताया कि सिविल डिफेंस के पास केन शील्ड, बॉडी आर्मर और हेलमेट हो सकते हैं, लेकिन इस बल के पास लाठियां नहीं होंगी। दंगा-रोधी पुलिस दूर रहकर स्थिति पर नजर रख सकती है और आम तौर पर जानमाल की, खास तौर पर सिविल डिफेंस की सुरक्षा कर सकती है। किरण बेदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि दंगा-रोधी पुलिस को तभी आना चाहिए जब सिविल डिफेंस की लाइन तोड़ी जा रही हो या खतरे में हो।

भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुआ ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज

ग्लास्गो, (हि.स.)

स्कॉटलैंड के ग्लास्गो स्थित हाइड्रो एरिना में गुरुवार रात रंगों, रोशनी, संगीत और सांस्कृतिक विरासत के अद्भुत संगम के बीच कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। पारंपरिक स्कॉटिश संस्कृति और आधुनिक तकनीक के शानदार मेल ने उद्घाटन समारोह को यादगार बना दिया।



हजारों दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों, आकर्षक दृश्य प्रभावों और खिलाड़ियों की शानदार परेड ने खेलों के महाकुंभ की बेहतरीन शुरुआत की। समारोह की शुरुआत स्कॉटलैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के साथ हुई। देश के महानतम खिलाड़ियों में शुमार दिग्गज ट्रैक साइकिलिस्ट सर क्रिस होय और प्रसिद्ध अभिनेता ग्रेग मैकह्यू लोकप्रिय ब्रिटिश विज्ञान-कथा श्रृंखला डॉक्टर हू के मशहूर टार्डिस बॉक्स के माध्यम से मंच पर पहुंचे। इस दौरान किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला की मौजूदगी ने समारोह की गरिमा को और बढ़ा दिया। टार्डिस को इस बार स्कॉटलैंड की कहानी और विरासत को दुनिया तक पहुंचाने के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद संगीत, नृत्य और आधुनिक तकनीक का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने पूरे एरिना को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्कॉटिश इलेक्ट्रॉनिक फोक संगीतकारों वाल्टोस की धुनों पर तैयार विशेष साउंडट्रैक के बीच 74 राष्ट्रमंडल खेल संघों के खिलाड़ी एक-एक कर एरिना में प्रवेश करते गए। एलईडी स्क्रीन पर हर दल का परिचय दिया गया, जबकि स्कॉटलैंड की प्राकृतिक वनस्पतियों से प्रेरित रंग-बिरंगे एनिमेशन के जरिए राष्ट्रमंडल बैटन को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। मेजबान स्कॉटलैंड का दल सबसे आखिर में मैदान में उतरा और घरेलू दर्शकों ने जोरदार तालियों और नारों के साथ उसका स्वागत किया। खिलाड़ियों की परेड ने पूरे समारोह का सबसे भावुक और आकर्षक पल पेश किया, जहां खेल भावना, एकता और राष्ट्रमंडल परिवार की विविधता साफ दिखाई दी। उद्घाटन समारोह में स्कॉटलैंड की लोककथाओं और इतिहास को भी आधुनिक अंदाज में मंच पर उतारा गया। प्रसिद्ध लोच नेस मॉन्स्टर की कहानी से लेकर ग्लास्गो की पहचान मानी जाने वाली 'वॉयस ऑफ टाइम' घड़ी तक, हर प्रस्तुति ने दर्शकों को स्कॉटलैंड की सांस्कृतिक यात्रा से रूबरू कराया। गायक नाथन इवांस के जोशीले प्रदर्शन, ग्लास्गो सेंट्रल स्टेशन पर आधारित रंगारंग नृत्य और शहर के जहाज निर्माण, वस्त्र उद्योग, रेल इंजन तथा भाप इंजनों की ऐतिहासिक विरासत को भी शानदार अंदाज में प्रस्तुत किया गया।



चाइना ओपन 2026 : अंतिम-16 में हारकर बाहर हुईं पी.वी. सिंधु

चांगझोउ, एजेंसी। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु का चाइना ओपन 2026 में सफर अंतिम-16 दौर में ही समाप्त हो गया। गुरुवार को खेले गए मुकाबले में मेजबान चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चेन यू फेई ने शानदार वापसी करते हुए सिंधु को 16-21, 22-20, 21-18 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सिंधु ने मुकाबले की शानदार शुरुआत करते हुए पहला गेम अपने नाम किया। हालांकि दूसरे गेम में उनके पास मैच खत्म करने के चार मौके थे, लेकिन वह उनका फायदा नहीं उठा सकीं और चेन ने लगातार पांच अंक जीतकर मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। पहले गेम में चेन ने 12-6 की बढ़त बना ली थी, लेकिन सिंधु ने शानदार वापसी करते हुए स्कोर 16-16 से बराबर किया और इसके बाद लगातार अंक जुटाकर 21-16 से गेम जीत लिया। दूसरे गेम में सिंधु पूरी तरह नियंत्रण में नजर आईं और 20-17 की बढ़त के साथ उनके पास चार मैच प्वाइंट थे। लेकिन इसी मोड़ पर चेन ने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार पांच अंक हासिल किए और 22-20 से गेम जीतकर मुकाबले को तीसरे गेम में पहुंचा दिया।

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बांग्लादेश को झटका, तेज गेंदबाज इबादत हुसैन बाहर

नई दिल्ली, एजेंसी

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज इबादत हुसैन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाएंगे।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इबादत अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण बांग्लादेश में ही रहेंगे और टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया का दौरा नहीं करेंगे। बांग्लादेश की टीम 13 अगस्त से डार्विन में शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 चक्र का हिस्सा है। फिलहाल बांग्लादेश डब्ल्यूटीसी अंकतालिका में चौथे स्थान पर है और इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगा। हालांकि इबादत की गैरमौजूदगी के बीच टीम को एक राहत भी मिली है। तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने ऑस्ट्रेलिया दौरे की बेहतर तैयारी के लिए श्रीलंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) से अपना नाम वापस ले लिया है। तस्कीन ने कहा, 'मेरा मुख्य लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी करना है। हमने जिम्बाब्वे में लगातार छह मैच खेले हैं।



नाहिद राणा और लिटन दास की फिटनेस पर नजर

बांग्लादेश के लिए एक और चिंता तेज गेंदबाज नाहिद राणा की फिटनेस है। उनके शरीर के साइड हिस्से में लगी चोट की स्कैन रिपोर्ट का टीम प्रबंधन को इंतजार है। वहीं अनुभवी बल्लेबाज लिटन दास भी पिंडली (काफ) की चोट से उबर रहे हैं और टीम को उम्मीद है कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उपलब्ध रहेंगे।

सीरीज का कार्यक्रम
पहला टेस्ट : 13-17 अगस्त, डार्विन
दूसरा टेस्ट : 22-26 अगस्त, मैके

निकोलस ओटामेंडी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को कहा अलविदा

ब्यूनस आयर्स, (हि.स.)

अर्जेंटीना के अनुभवी डिफेंडर निकोलस ओटामेंडी ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। इसके साथ ही 38 वर्षीय खिलाड़ी के 17 साल लंबे शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत हो गया।

इस दौरान उन्होंने अर्जेंटीना को 2022 फीफा विश्व कप और दो कोपा अमेरिका खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। ओटामेंडी ने अर्जेंटीना के लिए 139 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और चार फीफा विश्व कप में देश का प्रतिनिधित्व किया। वह हाल ही में अमेरिका में आयोजित फीफा विश्व कप 2026 में उपविजेता रही अर्जेंटीना टीम का भी हिस्सा थे। फाइनल में अर्जेंटीना को स्पेन के हाथों अतिरिक्त समय में 1-0 से हार का सामना करना पड़ा था। संन्यास की घोषणा करते हुए ओटामेंडी ने इंस्टाग्राम पर भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, आज मुझे अपने करियर के सबसे कठिन शब्द लिखने पड़ रहे हैं। किस्मत ने ऐसा लिखा कि मेरा आखिरी मैच विश्व कप फाइनल रहा।



वैभव दुनिया के सबसे युवा टी20आई अर्धशतक वीर

पहली ही गेंद पर विकेट, मयंक ने रचा इतिहास

यादव की यादगार वापसी; बतौर कप्तान श्रेयस की पहली जीत

हरारे, एजेंसी

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्डतोड़ अर्धशतक और तेज गेंदबाज मयंक यादव की शानदार वापसी की बदौलत भारत ने गुरुवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे को सात विकेट से हरा दिया। श्रेयस की कप्तानी में भारत की यह पहली जीत रही, जबकि इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 20 ओवर में सात विकेट पर 125 रन पर रोक दिया। जवाब में भारत ने 13.2 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 126 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और अभिषेक शर्मा केवल एक रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने आते ही मैच का रुख बदल दिया। बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर अपनाए और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला।

वैभव ने रिचर्ड एनगरावा और ब्लेसिंग मुजारबानी जैसे अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ शानदार शॉट लगाए। उन्होंने महज 19 गेंदों में चार चौकों और चार छक्कों की मदद से 50 रन ठोक दिए।



अय्यर के नाम पहली जीत

यह जीत कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए भी बेहद खास रही। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर लगातार छह टी20 मुकाबले हारने के बाद आखिरकार उनकी कप्तानी में भारत को पहली जीत मिली।

गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन और वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर भारत ने एकतरफा अंदाज में मुकाबला जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

मयंक की यादगार वापसी

करीब 21 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लौटे तेज गेंदबाज मयंक यादव ने अपनी वापसी को खास बना दिया। उन्होंने मैच की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच कराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई।

व्यापार

संक्षिप्त समाचार

इंडिगो एयरलाइन को 238 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा



नई दिल्ली, एजेंसी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की (अप्रैल-जून) पहली तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया है। कंपनी को अप्रैल-जून तिमाही में 238 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध घाटा हुआ है। कंपनी को पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 2,176.3 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ हुआ था। कंपनी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 25,614.1 करोड़ रुपये हो गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 21,542.6 करोड़ रुपये थी। इस दौरान कंपनी के कुल खर्च में भी वृद्धि हुई है। इंडिगो ने कहा कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव तथा पश्चिम एशिया में संकट का तिमाही की लाभप्रदता पर संयुक्त असर पड़ा, जिससे कंपनी को 2.4 अरब रुपये (238 करोड़ रुपये) का शुद्ध घाटा हुआ है। कंपनी के मुताबिक ईंधन की ऊंची कीमतों, विदेशी मुद्रा विनिमय में नुकसान और पश्चिम एशिया में जारी संकट का भी लाभ पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो की मूल कंपनी है। घरेलू विमानन बाजार में इंडिगो की हिस्सेदारी 66 फीसदी से अधिक है।

अमेरिका-ईरान तनाव से कच्चा तेल 98 डॉलर प्रति बैरल के पार

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट और अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एकबार फिर तेजी दर्ज हुई है। ब्रेंट क्रूड गुरुवार को 4 फीसदी बढ़कर 98 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जो पिछले छह हफ्तों का उच्चतम स्तर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज कारोबार के दौरान कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड 4.58 डॉलर यानी 4.87 फीसदी की तेजी के साथ 98.65 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जो पिछले 6 हफ्तों का उच्चतम स्तर है। वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई क्रूड) भी 3.69 डॉलर यानी 4.25 फीसदी की उछाल के साथ 90.52 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने देश में महंगाई और ऊर्जा संकट बढ़ा दिया है। इससे भारतीय मुद्रा रुपये और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के फ्लो पर असर पड़ने की संभावना है। वहीं, कच्चे तेल के महंगे होने से भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के रिटेल फ्यूल मार्जिन पर भारी दबाव पड़ा है, जिससे डीजल पर कंपनियों को प्रति लीटर 20.4 रुपये का घाटा हो रहा है।

सोने की चमक के साथ चांदी के भाव में भारी उछाल

नई दिल्ली, एजेंसी। घरेलू सर्राफा बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। भाव में आए उछाल के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना 2,100 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 2,190 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। वहीं चांदी के भाव में भी आज 5,200 रुपये प्रति किलोग्राम की जोरदार तेजी नजर आ रही है।

भाव में आए उछाल के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,46,420 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,46,570 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,34,310 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,34,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी तेजी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 2,40,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,46,570 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,460 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,46,420 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,34,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,46,470 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,360 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

देशभर में 10,389 किलोमीटर के नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर आवंटित

4,809 किमी सड़क निर्माण पूरा : केंद्र

नई दिल्ली, एजेंसी

देशभर में अब तक 10,389 किलोमीटर के नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स आवंटित की जा चुके हैं। इनमें से 4,809 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 5,580 किलोमीटर लंबाई के प्रोजेक्ट्स पर कार्य जारी है। यह जानकारी सरकार की ओर से संसद में दी गई।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने सभी निर्माणाधीन नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट्स की नियमित समीक्षा के लिए प्रोजेक्ट, राज्य और केंद्र स्तर पर एक समन्वित व्यवस्था बनाई है। इसमें संबंधित राज्य सरकारों सहित सभी पक्षकारों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।



केंद्रीय मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे की सबसे अधिक 1,340 किलोमीटर लंबाई के प्रोजेक्ट्स आवंटित किए गए हैं। इनमें से 1,192 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 148 किलोमीटर पर काम चल रहा है। अन्य प्रमुख राज्यों में पंजाब शामिल है, जहां 923 किलोमीटर लंबाई के प्रोजेक्ट्स आवंटित किए गए हैं, जिनमें 774 किलोमीटर पर निर्माण कार्य जारी है।

वहीं, आंध्र प्रदेश में 893 किलोमीटर लंबाई के प्रोजेक्ट्स आवंटित किए गए हैं, जिनमें 308 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है और 585 किलोमीटर पर काम जारी है। उत्तर प्रदेश में 884 किलोमीटर लंबाई के प्रोजेक्ट्स आवंटित किए गए हैं, जिनमें 388 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 496 किलोमीटर पर कार्य चल रहा है। हरियाणा में 839 किलोमीटर लंबाई के प्रोजेक्ट्स आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 615 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा, गुजरात में आवंटित 764 किलोमीटर कॉरिडोर नेटवर्क में से 605 किलोमीटर का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

सरकार ने कई कदम उठाए

प्रोजेक्ट्स के तेजी से क्रियान्वयन के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें 'भूमि राशि' पोर्टल और जीआईएस आधारित भूमि अधिग्रहण योजनाओं के जरिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाना तथा 'परिवेश' पोर्टल को उन्नत कर पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरियां तेजी से उपलब्ध कराना शामिल है। सरकार ने रेलवे से रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) के लिए जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग (जीएडी) की ऑनलाइन स्वीकृति की व्यवस्था भी शुरू की है।

इसके साथ ही, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों के जरिए परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं का समाधान किया जा रहा है। सरकार के अनुसार, निरंतर निगरानी और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के कारण देशभर में नेशनल हाइवे, हाई-स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन में तेजी आई है।

भारतीय रेलवे ने हाई-डेंसिटी रूट पर तीसरी लाइन के लिए 440 करोड़ रुपए की परियोजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे के निमपुरा वेस्ट आउटर केबिन और मिदनापुर के बीच 14.52 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन बिछाने की 440 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य इस व्यस्त रेल कॉरिडोर की क्षमता बढ़ाना और यात्री व मालगाड़ियों की आवाजाही को सुगम बनाना है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, यह परियोजना भारतीय रेलवे द्वारा हाई-डेंसिटी रूट्स पर नेटवर्क क्षमता बढ़ाने की व्यापक



योजना का हिस्सा है। इसके पूरा होने के बाद इस मार्ग पर हर वर्ष अतिरिक्त 3.52 मिलियन टन (एमटीपीए) माल ढुलाई संभव हो सकेगी, जिससे उद्योगों और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को बड़ा लाभ मिलेगा। यह सेक्शन हाई यूटिलाइजेशन नेटवर्क (एचयूएन-2) का हिस्सा है। फिलहाल निमपुरा वेस्ट आउटर केबिन से गोकुलपुर तक का हिस्सा सिंगल लाइन है, जबकि डबलिंग का काम पहले से जारी है। तीसरी लाइन बनने से इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्ग की क्षमता और परिचालन लचीलापन दोनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। इस रेल मार्ग से यात्री ट्रेनों के साथ-साथ मैंगनीज, लौह अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद, चूना पत्थर, जिप्सम, उर्वरक, खाद्य तेल, केमिकल सॉल्ट, चारकोल, सीमेंट, बैलेस्ट और राख जैसी कई महत्वपूर्ण वस्तुओं का परिवहन होता है।

भारत में लॉन्च हुई मर्सिडीज-एएमजी ई 53 हाइब्रिड 4एमएटीआईसी प्लस

नई दिल्ली। लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने गुरुवार को देश में मर्सिडीज-एएमजी ई 53 हाइब्रिड 4एमएटीआईसी+ लॉन्च कर दी है। यह भारत में कंपनी की पहली इलेक्ट्रिफाइड एएमजी ई-क्लास सेडान है। इसके साथ ही कंपनी ने अपनी प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईवी) रेंज को और मजबूत किया है। यह मॉडल कंपनी की 'पावरट्रेन एग्नॉस्टिक' रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत ग्राहकों को अलग-अलग तकनीक वाले वाहन चुनने का विकल्प दिया जा रहा है।

नई एएमजी ई 53 हाइब्रिड 4एमएटीआईसी+ की परफॉर्मेंस एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 1.45 करोड़ रुपए और रेसिंग एडिशन की कीमत 1.48 करोड़ रुपए

कीमत 1.45 करोड़ रुपए से शुरू

रखी गई है। यह कार एएमजी की दमदार परफॉर्मेंस को प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक की बेहतर ईंधन दक्षता और रोजमर्रा की उपयोगिता के साथ जोड़ती है। कंपनी का कहना है कि वह ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुसार इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई), इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड जैसे कई पावरट्रेन विकल्प उपलब्ध करा रही है, ताकि वे अपनी पसंद और उपयोग के हिसाब से वाहन चुन सकें।

मर्सिडीज-बेंज इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ संतोष अय्यर ने कहा कि ई-क्लास भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की सबसे लंबे समय से मौजूद मॉडल सीरीज में से एक है। उन्होंने कहा कि एएमजी ई 53 हाइब्रिड 4 एमएटीआईसी+ परफॉर्मेंस, रोजमर्रा की उपयोगिता और इलेक्ट्रिक दक्षता का बेहतरीन संतुलन पेश करती है, जिससे ई-क्लास पोर्टफोलियो और भी मजबूत हो गया है। उन्होंने कहा कि यह नई परफॉर्मेंस सेडान ट्रैक पर दमदार प्रदर्शन के साथ-साथ रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए भी उपयुक्त है और एएमजी ग्राहकों की दोनों जरूरतों को पूरा करती है।

नई एएमजी ई 53 हाइब्रिड 4एमएटीआईसी+ में 3.0 लीटर इनलाइन 6-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 330 किलोवाट (449 हॉर्सपावर) की शक्ति पैदा करता है। इसके साथ 120 किलोवाट का इलेक्ट्रिक मोटर भी लगाया गया है।

निवेशकों के 2.99 लाख करोड़ डूबे

लगातार चौथे दिन आई घरेलू शेयर बाजार में गिरावट

नई दिल्ली, एजेंसी

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में लगातार तेजी की वजह से घरेलू शेयर बाजार आज लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। आज के कारोबार की शुरुआत भी कमजोरी के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद दिन के पहले सत्र में खरीदारों ने लिवाली का जोर बना कर रिकवरी की कोशिश भी की, लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं हो सकी।

दोपहर 11 बजे के बाद बाजार में चौतरफा बिकवाली का दबाव बन गया, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की कमजोरी बढ़ती चली गई। सेंसेक्स इंट्रा-डे में 600 अंक से अधिक टूट गया। निफ्टी ने भी इंट्रा-डे में लगभग 190 अंक तक गोता लगाया। हालांकि, आखिरी आधे घंटे के कारोबार में मामूली खरीदारी होने की वजह से इन दोनों सूचकांकों ने निचले स्तर से कुछ हद तक रिकवरी करने में सफलता भी हासिल की। पूरे दिन के



कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.47 प्रतिशत और निफ्टी 0.53 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुए।

बीएसई का सेंसेक्स आज 239.95 अंक यानी 0.31 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 76,515.10 अंक के स्तर पर खुला। बाजार खुलने के कुछ देर बाद खरीदारों ने लिवाली शुरू कर दी, जिससे इस सूचकांक की स्थिति में सुधार होने लगा। खरीदारी के सपोर्ट से सेंसेक्स दोपहर 11 बजे के करीब ओपनिंग लेवल से 210 अंक से ज्यादा सुधर कर 76,726.66 अंक तक आ गया, लेकिन इसके बाद बाजार में बिकवाली का दबाव बन गया।

लगातार हो रही बिकवाली के कारण यह सूचकांक शाम तीन बजे के थोड़ी देर पहले 603.07 अंक यानी 0.79 प्रतिशत टूट कर 76,151.98 अंक के स्तर तक गिर गया।

तीन देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर रोमानिया पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू

फार्मा, ऊर्जा और कृषि में बढ़ेगा सहयोग, भारत-रोमानिया ने तय किए बड़े लक्ष्य



बुखारेस्ट,एजेंसी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वी यूरोप की तीन देशों की राजकीय यात्रा के तहत रोमानिया पहुंचीं। विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को भारत और रोमानिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।

भारत और रोमानिया ने द्विपक्षीय साझेदारी के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में आर्थिक सहयोग को रेखांकित किया और अगले तीन वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। यह ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक यात्रा पर रोमानिया पहुंचीं। यह तीन दशकों में किसी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की पहली यात्रा है।



साइबर कूटनीति पर विशेष प्रशिक्षण शामिल

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि रक्षा सहयोग भी साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और दोनों देशों ने नियमित आदान-प्रदान, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच करीबी सहयोग के जरिए इस क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। भारत सरकार ने रोमानिया के लिए आईटीईसी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण के अवसरों को दोगुना करने का फैसला किया है। इनमें एआई से संबंधित पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। हमारे विदेश सेवा संस्थान ने रोमानियाई राजनयिकों को आगामी पेशेवर पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए हैं। इन कार्यक्रमों में एआई और साइबर कूटनीति पर विशेष प्रशिक्षण भी शामिल होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत भारत और रोमानिया के बीच जारी सहयोग का स्वागत किया और आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन तथा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने के रोमानिया के इरादे का भी स्वागत किया।

राष्ट्रपति डैन का भारत में स्वागत

मुर्मू ने बताया कि जब वर्ष 2028 में भारत और रोमानिया के बीच राजनयिक संबंधों के 80 वर्ष पूरे होंगे, तब दोनों देशों ने इस अवसर को भारत-रोमानिया नवाचार वर्ष के रूप में मनाने पर सहमति जताई है। नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और शांति, संवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति साझा प्रतिबद्धता दोहराई, ताकि वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने रोमानिया द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया और राष्ट्रपति डैन का भारत में स्वागत करने की उम्मीद जताई। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही मुझे राष्ट्रपति डैन का नई दिल्ली में स्वागत करने का अवसर मिलेगा।

संक्षिप्त समाचार

ईरान पर यूएस ने लगातार 13वें दिन भी हवाई हमले किए

ईरान, एजेंसी। ईरान की सेना ने बहरीन और जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य परिसरों पर ड्रोन से हमले का दावा किया है। बहरीन के शेख ईसा एयर बेस पर ईंधन भंडारण टैंकों, उपकरण गोदामों और सैनिकों के रहने के क्वार्टरों को निशाना बनाया गया। वहीं, जॉर्डन के मुवफ्फक साल्टी बेस पर एयरक्राफ्ट हैंगर और मेंटेनेंस सुविधाओं पर हमले किए गए। ईरान ने चेतावनी दी है कि उसके हितों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्षेत्रीय सुरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचाएगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि गाजा में तथाकथित युद्धविराम के बावजूद, आम नागरिकों को हर दिन भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस्राइल द्वारा गाजा पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के कारण लोग अपने घरों और समुदायों में दैनिक जीवन के सामान्य कार्य करते हुए भी मारे जा रहे हैं। वहां लोगों की स्थितियां असहनीय बनी हुई हैं और भयानक बीमारियां फैल रही हैं, जिससे मानवीय सहायता कार्यों में भारी बाधा आ रही है। इस लंबे समय से चले आ रहे मानवीय कष्ट का अंत होना ही चाहिए। अमेरिकी सेना ईरान पर लगातार हवाई हमले कर रही है। इन हमलों में ईरान के अहवाज, रामशिर और शलमचेह समेत कई शहरों पर अमेरिकी मिसाइलें गिरी हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इन हमलों में 27 जून से अब तक 55 लोगों की जान जा चुकी है और 629 लोग घायल हुए हैं। जंग का असर आसपास के खाड़ी देशों पर भी पड़ रहा है। हाल ही में कुवैत की सीमा पर ड्रोन हमला हुआ, जॉर्डन ने अपनी हवाई सीमा में कई मिसाइलों और ड्रोनों को नष्ट किया, वहीं बहरीन में खतरे के सायरन बजाए गए।

बाल सुरक्षा कानूनों के समर्थक स्विस नेता पर रेप का आरोप



स्विट्जरलैंड, एजेंसी। स्विट्जरलैंड में बाल सुरक्षा से जुड़े कई कानूनों का समर्थन कर चुके दक्षिणपंथी नेता पैट्रिक फ्राई पर नाबालिग से रेप समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। अभियोजकों ने 57 साल के पूर्व स्विस पीपुल्स पार्टी नेता के लिए उम्रकैद की मांग की है। आरगाउ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ऑफिस के मुताबिक, फ्राई पर अपनी पार्टनर और उसकी नाबालिग बेटी को कथित तौर पर नशीली दवा देकर व्यवस्थित रूप से यौन शोषण करने का आरोप है। उन पर एक अन्य वयस्क महिला को नशीली दवा देने और उसका रेप करने का भी आरोप है। अभियोजकों के मुताबिक, पीड़ितों को दी गई नशीली दवाओं के कारण उनकी जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया था। अभियोजन कार्यालय ने कहा कि इन पदार्थों के इस्तेमाल से पीड़ित कभी भी दम घुटने की वजह से मर सकते थे। अभियोजकों का आरोप है कि फ्राई ने पीड़ितों की संभावित मौत को स्वीकार किया था। इसी आधार पर उन पर हत्या की कोशिश के कई मामले भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस जांच 2023 में शुरू हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, नाबालिग लड़की की मां ने कथित तौर पर नेता को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ने के बाद पुलिस को फोन किया था। इसके कुछ समय बाद फ्राई को गिरफ्तार कर लिया गया। वह तब से हिरासत में है। अभियोजकों के मुताबिक, जांच के दौरान पुलिस को कथित अपराधों से जुड़े कई सबूत मिले, जिनमें पोर्नोग्राफिक वीडियो और तस्वीरें भी शामिल हैं।

चीन की आक्रामकता से बढ़ा तनाव

मनीला, एजेंसी। मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के कुछ दिनों बाद दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ गया। बैठक में स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई थी। इसके बाद चीन के तटरक्षक बल ने बाजो डे मासिनलोक के पास फिलीपीनी जहाजों पर पानी की बौछार की और खतरनाक तरीके से उनकी दिशा में जहाज चलाए। पश्चिमी फिलीपीन सागर के लिए फिलीपीन तटरक्षक बल के प्रवक्ता रियर एडमिरल जे तारिएला द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए बयान के अनुसार, शुक्रवार को तनाव उस समय बढ़ गया जब चीन के तटरक्षक बल ने बीडीएम के पास समुद्री अभियान चला रहे फिलीपीन तटरक्षक बल और मत्स्य एवं जलीय संसाधन ब्यूरो के जहाजों पर कई बार पानी की बौछार की और खतरनाक तरीके से जहाज चलाए। ये घटनाएं उस समय हुईं जब फिलीपीन तटरक्षक बल और मत्स्य एवं जलीय संसाधन ब्यूरो काडिवा नग बागोंग बायानिंग मांगिंगिस्दा कार्यक्रम को लागू कर रहे थे। यह सरकारी पहल फिलीपीनी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को ईंधन सब्सिडी और जरूरी सामान उपलब्ध कराने तथा पारंपरिक मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में काम कर रहे फिलीपीनी मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

करीम खान को ICC अभियोजक पद से हटाने पर आज वोटिंग :125 में से 63 देशों का समर्थन जरूरी



आस्ट्रेलिया, एजेंसी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के सदस्य देश शुक्रवार को मुख्य अभियोजक करीम खान को पद से हटाने पर वोट करेंगे। खान पर यौन दुराचार के आरोप हैं। वे इन आरोपों से इनकार करते हैं। 56 साल के खान को मई 2025 से जांच पूरी होने तक स्वैच्छिक अवकाश पर रखा गया था। जून से वे निलंबित हैं। ICC की गवर्निंग बॉडी के फैसले के बाद अब उन्हें हटाने के लिए गुप्त मतदान होगा। ICC की गवर्निंग बॉडी के अधिकारियों के मुताबिक, खान को इसलिए हटाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक जूनियर स्टाफ सदस्य के साथ अनुचित यौन संबंध बनाकर गंभीर दुराचार किया। वोटिंग भारतीय समय के अनुसार रात करीब 12.30 बजे शुरू होने की संभावना है। परिणाम रात करीब 3 बजे घोषित होने की उम्मीद है। फ्रांस ने गुरुवार को कहा कि वह खान को हटाने के पक्ष में वोट करेगा। नीदरलैंड्स ने भी उनके निष्कासन का समर्थन करने की बात कही है। नीदरलैंड्स में ही ICC का मुख्यालय है।

'तीर्थयात्रा' रोकने के लिए ऑस्ट्रिया ने इमारत बदली

फ्रांस, एजेंसी। एजर्मनी की सीमा के पास ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ एम इन शहर में एडॉल्फ हिटलर के जन्मस्थान की इमारत ने बुधवार से नई भूमिका शुरू कर दी। अब यहां पुलिस स्टेशन बनाया गया है। ऑस्ट्रिया सरकार को उम्मीद है कि इससे यह जगह नव-नाजियों के लिए 'तीर्थस्थल' नहीं बनेगी। यह इमारत कई सालों तक निजी स्वामित्व में रही थी और यहां दिव्यांग लोगों के लिए काम करने वाली एक चैरिटी संस्था भी थी।

अमेरिका ने भारत पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया

जबरन मजदूरी से बने सामान को लेकर कार्रवाई, 60 देशों पर एक्शन

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी

अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह फैसला शुक्रवार से लागू हो गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निर्देश पर अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने फोर्स्ड लेबर (जबरन मजदूरी) से बने सामान के आयात को लेकर 60 देशों पर कार्रवाई की है। अमेरिका ने इन देशों पर 10% से 12.5% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। भारत उन 17 देशों में शामिल है, जिन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। वहीं बाकी 43 देशों पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने यह कार्रवाई ट्रेड एक्ट-1974 की धारा 301 के तहत की है। भारत के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मेक्सिको, पाकिस्तान और श्रीलंका समेत कई देशों को 10% टैरिफ वाले समूह में रखा गया है। अमेरिका का कहना है कि इन देशों ने फोर्स्ड लेबर से बने सामान पर प्रतिबंध लगाया है या ऐसा करने की दिशा में कदम उठाए हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। ऐसे में अतिरिक्त 10% टैरिफ से उन सेक्टरों पर ज्यादा असर पड़ सकता है, जिनकी अमेरिकी बाजार पर निर्भरता अधिक है। इनमें टेक्सटाइल और गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर उत्पाद, कृषि एवं फूड प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स और कुछ मैन्युफैक्चरिंग आइटम शामिल हैं। अतिरिक्त टैरिफ लगने से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। इससे खरीदार दूसरे देशों के विकल्प तलाश सकते हैं या भारतीय निर्यातकों पर कीमत घटाने का दबाव बढ़ सकता है।



सेक्शन 301 के तहत अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया

सेक्शन 301 अमेरिका के ट्रेड एक्ट-1974 का एक प्रावधान है। इसके तहत अमेरिकी सरकार को यह अधिकार मिलता है कि अगर किसी देश की व्यापारिक नीतियां अमेरिकी कारोबार या उद्योगों के लिए अनुचित, भेदभावपूर्ण या नुकसानदायक मानी जाएं, तो वह उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस कार्रवाई में अतिरिक्त टैरिफ लगाना, आयात पर प्रतिबंध लगाना या दूसरे व्यापारिक प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। जांच की जिम्मेदारी अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की होती है। जांच के दौरान संबंधित देश से जवाब मांगा जाता है और जरूरत पड़ने पर बातचीत भी की जाती है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की मंजूरी से कार्रवाई लागू होती है।

भारत को 12.5% की जगह 10% टैरिफ क्यों मिला

शुरुआत में भारत पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था। हालांकि बाद में भारत सरकार की ओर से श्रम मानकों और सप्लाई चेन की निगरानी से जुड़े कुछ नीतिगत सुधारों तथा अमेरिका के साथ लगातार बातचीत के बाद इसे घटाकर 10% कर दिया गया। फेडरल नोट में कहा गया है कि जून में प्रस्तावित टैरिफ घोषित होने के बाद भारत ने 14 जून को अपनी विदेशी व्यापार नीति में संशोधन किया। अमेरिका का मानना था कि भारत ने श्रमिक अधिकारों की निगरानी, नियमों के पालन और सप्लाई चेन में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। इसी आधार पर प्रस्तावित टैरिफ में 2.5% की राहत दी गई। 10% टैरिफ लागू रहने का मतलब है कि भारत को पूरी छूट नहीं मिली है। यानी अमेरिका अब भी चाहता है कि भारत श्रम मानकों और फोर्स्ड लेबर से जुड़े नियमों को और प्रभावी ढंग से लागू करे। हालांकि 12.5% के बजाय 10% टैरिफ से भारतीय निर्यातकों पर पड़ने वाला अतिरिक्त लागत का बोझ कुछ कम होगा।

पाकिस्तान को भारत की दो टूक

पड़ोसियों पर आरोप नहीं, आतंकवाद का ढांचा खत्म करो

नई दिल्ली, एजेंसी

भारत ने 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच बैठक में कश्मीर और सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की।

नई दिल्ली ने पाकिस्तान की टिप्पणियों को 'निराधार और अनावश्यक' बताते हुए कहा कि पाकिस्तानी प्रतिष्ठान अपने घरेलू संकट और वैश्विक आतंकी नेटवर्क के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में अपनी स्थापित भूमिका से ध्यान भटकाने की एक और 'निरर्थक कोशिश' कर रहा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पिछले दो दिनों में फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान के तहत उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठकों में हिस्सा लिया। इशाक डार की टिप्पणियों पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर बहुपक्षीय मंच का जानबूझकर गलत इस्तेमालकरते हुए झूठ फैलाने और राज्य प्रायोजित दुष्प्रचार को बढ़ावा देने की कोशिश की है।



ध्यान भटकाने की एक निरर्थक कोशिश

भारत ने कहा कि पड़ोसी देशों पर आरोप लगाने और वैश्विक मंचों का दुरुपयोग करने के बजाय पाकिस्तान को अपनी जनता के हित में अपनी जमीन पर आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को खत्म करने और अपने आंतरिक मामलों को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए। हम पाकिस्तान द्वारा आधिकारिक रूप से प्रायोजित दुष्प्रचार फैलाने की लगातार जारी नीति की भी कड़ी निंदा करते हैं, जिसे अक्सर फितना अल-हिंदुस्तान जैसे धार्मिक शब्दों के इस्तेमाल के जरिए पेश किया जाता है। यह पाकिस्तानी प्रतिष्ठान की अपने आंतरिक संकट और वैश्विक आतंकी नेटवर्क के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में उसकी अच्छी तरह से स्थापित भूमिका से ध्यान भटकाने की एक निरर्थक कोशिश है।

फ्रांस : 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा

पेरिस, एजेंसी



फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा।

एक पोस्ट में उन्होंने सांसदों के समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा,मैंने इसका वादा किया था और अब इस पर मतदान हो चुका है: स्कूल दोबारा खुलने के समय से 15 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सांसदों को धन्यवाद। इसके बाद इस उपाय को ठोस रूप देने और हमारे बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इस कदम के साथ फ्रांस यूरोपीय संघ का ऐसा पहला देश बन गया है, जिसने इस तरह की आयु सीमा लागू की है। इससे पहले जून में, यूनाइटेड किंगडम ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने एक वीडियो संदेश में इसे समय की जरूरत और देश के लिए एक बड़ा फैसला बताया था। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा था कि सोशल मीडिया बच्चों को लगातार स्क्रॉल करने के चक्र में फंसा सकता है।

यरुशलम में भारतीय व्यक्ति की हत्या

कटामोन, एजेंसी। यरुशलम के कटामोन इलाके में 40 साल के भारतीय व्यक्ति का शव एक घर में मिला। पुलिस के मुताबिक, शव फर्श पर पड़ा था और उसके आसपास काफी खून था। इजराइल पुलिस ने हत्या के शक में 31 साल के एक इजराइली नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में मामला आपराधिक प्रकृति का लग रहा है। मृतक और संदिग्ध की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। यरुशलम जिला कमांडर अवशालोम पेलेड भी मौके पर पहुंचे और जिला अधिकारियों के साथ स्थिति का आकलन किया। पेलेड ने शुरुआती आकलन के बाद जांच जारी रखने के निर्देश दिए। पुलिस के मुताबिक, मृतक 40 साल का भारतीय प्रवासी कामगार था।

गुजरात में एनडीआरएफ ने बाढ़ के पानी से 67 लोगों को बचाया

नवसारी, एजेंसी

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने गुजरात के नवसारी जिले के सरीखुराड गांव में बाढ़ के पानी से 67 लोगों को बचाया है, जिनमें 25 महिलाएं और 22 बच्चे शामिल हैं।

एनडीआरएफ के अनुसार, ग्रामीणों के बाढ़ के कारण फंसे होने की जानकारी नागरिक प्रशासन से मिलने के बाद छठी बटालियन द्वारा बचाव अभियान शुरू किया गया। एनडीआरएफ ने कहा कि बचाव अभियान फिलहाल जारी है। इस बीच, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर रख रहे हैं।

सांघवी जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए नवसारी पहुंचे और अधिकारियों को निर्देश दिया कि बचाव, राहत, निकासी और सार्वजनिक सुरक्षा उपायों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राहत प्रयासों को मजबूत करने और प्रभावित नागरिकों को समय पर बचाव और सहायता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से वलसाड जिले में 10 वरिष्ठ अधिकारियों को भी तैनात किया है। वलसाड जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान तेज प्रयासों के साथ जारी है।



ग्रामीण क्षेत्रों से 2,603 लोगों को बचाया

तापी जिले में अत्यधिक भारी बारिश के बाद डोलवन तालुका के धोदियावाड़ फलिया में बाढ़ का पानी भर जाने से फंसे 11 ग्रामीणों को एसडीआरएफ ने बचाया। सूरत शहर में आपातकालीन सेवाएं चौबीसों घंटे बचाव और राहत अभियान चला रही हैं। लिम्बायत के गीता नगर, वराछा के शीतला माता मंदिर क्षेत्र और उधना के कृष्णा नगर से 50 से अधिक निवासियों को बचाया गया। कुल मिलाकर, सूरत शहर के 2,244 प्रभावित निवासियों और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के 2,603 लोगों को बचाकर राहत केंद्रों और अन्य सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

दिल्ली में हुई अहम बैठक

आतंकवाद और संगठित अपराध पर ब्रिक्स देशों का फोकस

नई दिल्ली, एजेंसी

ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित ब्रिक्स गृह मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें सदस्य देशों ने सुरक्षा, आतंकवाद रोधी, संगठित अपराध से मुकाबला, साइबर सुरक्षा और अन्य साझा चुनौतियों सहित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

भारत में ईरान के दूतावास ने ङ्क पर एक पोस्ट में कहा कि मोमेनी ने बैठक में भाग लिया, जिसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के आंतरिक और गृह मंत्रियों को साझा सुरक्षा चिंताओं पर समन्वय मजबूत करने के लिए एक साथ लाया गया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के आंतरिक मंत्री डॉ. एस्कंदर मोमेनी ने नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स गृह मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।



सहयोग के लिए एक उपयोगी मंच

मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, भाग लेने वाले देशों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को अपनाने की उम्मीद है, जिसमें आपदा लचीलापन मजबूत करने, संस्थागत सहयोग बढ़ाने और डीआरआर कार्य योजना को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की जाएगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ने वैश्विक आपदा लचीलापन को मजबूत करने के लिए समावेशी शासन, विज्ञान-आधारित नीति निर्माण, संस्थागत क्षमता निर्माण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया है। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात। यह वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व वाले समकालीन मुद्दों और वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक शासन के मुद्दों पर परामर्श और सहयोग के लिए एक उपयोगी मंच के रूप में कार्य करता है।

एक संयुक्त कार्यबल की स्थापना की

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में होने वाली डीआरआर बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख आपदा लचीलापन, जलवायु अनुकूलन, सतत विकास और आपदा जोखिम प्रबंधन में सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक साथ आएंगे। बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय के तहत आयोजित की जा रही है और इसका ध्यान जलवायु-स्मार्ट और आपदा-लचीली बुनियादी ढांचा प्रणालियों, साझेदारी, नवाचार और लचीले विकास के लिए वित्तपोषण को आगे बढ़ाने पर होगा। ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण सहयोग 2016 के उदयपुर घोषणा से विकसित हुआ है, जिसने आपदा प्रबंधन पर एक संयुक्त कार्यबल की स्थापना की थी, और 2024 की कजान घोषणा तक पहुंचा, जिसने ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह को संस्थागत रूप दिया और ब्रिक्स डीआरआर कार्य योजना (2025-2028) को अपनाया।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, विनय मिश्रा के लिए मुद्रक घनश्याम मधुकर गोसावी द्वारा एस.आर. पब्लिकेशन, मोहन अर्जुन कंपाउंड गोदाम नं. 8/9/10 निकट घरटनपाडा, वैशाली नगर, मुंबई 400068 से मुद्रित एवं प्लॉट नं.-3बी, चारभुजा मार्केट लिंक रोड, बोरीवली (पश्चिम) मुंबई से प्रकाशित। संपादक : श्रीमती शोभना मिश्रा, स्थानीय संपादक : डॉ. राखी सावलानी *, मो. 9425910888, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इन्दौर रहेगा) *पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।